04 - असंभव है इन परिवर्तनों को रोक पाना

05 - सितारों की भीड़ से अलग 'सितारे जमीन पर'

A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 24 जून, 2025

06 - बारिश से कटाव बढ़ने से प्रभावित हो सकता है मार्ग

07 - स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, सेवा गुणवत्ता और जनविश्वास का...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 285, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

बिहार चुनाव 2025 : क्या नीतीश का विकल्प बन पायेंगे चिराग?

शैलेश

बिहार चुनाव 2025 में लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) के प्रमुख चिराग पासवान की चर्चा जोर पकड़ रही है। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प बताया जा रहा है। बिहार में नेताओं की एक नयी पीढ़ी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का विकल्प बन कर खड़ी हो रही है। राज्य की राजनीति पर करीब चार दशकों से लालू और नीतीश का दबदबा रहा है। नब्बे के दशक में पिछड़ों के लिए आरक्षण की आंधी में लालू मुख्यमंत्री बने और करीब 15 सालों तक सत्ता में रहे। उसके बाद अति पिछड़ा और अति दलित का झंडा उठाकर नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और अब तक बने हुए हैं। चारा घोटाला में सजा के चलते लालू सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन अपनी विरासत बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी।

नीतीश के चेहरे पर भी उम्र की समस्याएं दिखायी दे रही हैं। उनके बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति में नहीं आए हैं। उनकी पार्टी जेडी यू में भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है। अक्टूबर-नवंबर के विधानसभा चुनावों के बाद उनकी विदाई की खबरें तेजी से चल रही हैं। नयी पीढ़ी के चार-पांच नेता अब उनका विकल्प बनने की तैयारी में लगे हैं। उनमें सबसे आगे लालू के बेटे तेजस्वी यादव हैं। वो नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बन गए थे। अब विपक्ष के नेता हैं।

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी अलग पार्टी बनाकर लालू-नीतीश का विकल्प बनने के जंग में जुटे हैं। बीजेपी ने पिछड़े नेता सम्राट चौधरी को आगे किया है, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट, पूर्व समाजवादी नेता और एक समय लालू और नीतीश के सहयोगी शकुनि चौधरी के बेटे हैं। कांग्रेस ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आगे किया है। लेकिन बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे ज़्यादा आतुर दिखायी दे रहे हैं चिराग पासवान। चिराग,पूर्व केंद्रीय मंत्री राम बिलास पासवान के बेटे हैं। वो कई बार घोषणा कर चुके हैं कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ कर बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने का उनका इरादा छुपा हुआ नहीं है।

चिराग दलित हैं और उन्होंने अपने पिता राम बिलास पासवान की विरासत को अच्छी तरह संभाल लिया है। लेकिन नीतीश ने दलितों को दलित और अति दलित में बांट दिया है। पासवान बिहार में दलितों की अपेक्षाकृत समृद्ध जाति है। अरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाली दलित जातियों में पासवान भी शामिल हैं। राज्य में इनकी आबादी करीब 5 प्रतिशत है। 2020 में राम बिलास पासवान की मृत्यु के बाद एनडीए ने चिराग को हाशिए पर धकेल कर राम विलास के भाई पशुपति पारस को आगे कर दिया था। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बंट गयी। पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गयी। लेकिन चिराग हार नहीं माने और बिहार में घूम घूम कर पार्टी को फिर से संगठित किया। उनका आरोप था कि उन्हें नीतीश कुमार के कहने पर एनडीए में किनारे किया गया। बदला लेने के लिए 2020 के विधान सभा चुनावों में चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडी यू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए।

इस चुनाव में जेडी यू को काफ़ी नुक़सान हुआ। उनके विधायकों की संख्या 43 पर सिमट गयी। यह अलग बात है कि 135 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी चिराग की पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पायी। 2024 के लोक सभा चुनाव में चिराग की एनडीए में वापसी हुई। उन्हें पाँच सीटें मिलीं। सभी सीटें जीत कर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह बना ली। इसके बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित है। विधानसभा में वो 20-25 से ज़्यादा सीटें जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनकी एक समस्या ये भी है कि अति दलितों के नेता जीतन राम मांझी बन चुके हैं। परिवार में उनके चाचा पशुपति पारस बाग़ी हो चुके हैं। वो एन डी ए के ख़िलाफ़ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन चिराग अब नीतीश कुमार का विकल्प बनने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं।

नए नेताओं में सबसे बड़ी ताक़त बन कर प्रशांत किशोर उभरे हैं। प्रशांत अपनी जन सुराज पार्टी के ज़रिए बिहार में जातीय राजनीति को विकास, राज्य का औद्योगीकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ़ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो सवर्ण हैं। जातीय गणित में उलझे बिहार को रोज़गार और शिक्षा की तरफ़ मोड़ना आसान नहीं है। प्रशांत का असर युवा वर्ग पर दिखायी दे रहा है लेकिन वो वोट में बदल पाएगा या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को आगे करके नया चेहरा तो पेश कर दिया लेकिन कन्हैया भी सवर्ण हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों और अति पिछड़ों में कांग्रेस की पैठ बहुत कम है। कांग्रेस के लिए फिलहाल आरजेडी की बैसाखी जरूरी है। बीजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अति पिछड़े वर्ग से हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी लालू और नीतीश के सहयोगी थे। सम्राट भी जेडी यू और आरजेडी में रह चुके हैं। 2017 में वो बी जेपी में शामिल हुए। उनमे नीतीश जैसी चमक नहीं है। बीजेपी उन्हें नीतीश के समानांतर खड़ा करने की कोशिश कर चुकी है।

नीतीश का अति पिछड़ा, अति दलित और महिला आधार कमजोर पड़ा है लेकिन उनके कद का कोई नेता अब भी नहीं है। इसलिए वो बीजे की मजबूरी बने हुए हैं। करीब बीस वर्षों के साथ में बीजेपी सिर्फ़ इतना हासिल कर पाई है कि नीतीश बीजेपी के बड़े सहयोगी से छोटे सहयोगी बन गए हैं।

कुछ समय पहले सी वोटर नाम की संस्था ने बिहार के नेताओं की लोकप्रियता का सर्वेक्षण किया। इसका नतीजा चौंकाने वाला था। इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए 36 प्रतिशत लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया। प्रशांत किशोर 17, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 13 और चिराग पासवान सिर्फ 6 फीसदी लोगों की पसंद हैं। सर्वे में शामिल आधे से ज़्यादा लोगों ने सरकार से नाखुशी जाहिर की और चुनावों के बाद बदलाव की इच्छा ज़ाहिर की।

सी वोटर के मुखिया यशवंत देशमुख ने इस सर्वे के बाद टिप्पणी की कि ये लोगों की इस वक्त की इच्छा है, लेकिन ये वोट में बदल जाय जरूरी नहीं है। इतना तो साफ़ है कि चिराग के लिए नीतीश का विकल्प बनना आसान नहीं है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

पुरखिनों से लोक पाया
गीत रचती जा रही हूँ
इसलिये मैं गा रही हूँ।
श्लोक झरते नीम से
देवता पीपर बसे
आते हैं पुरखे हमारे
हर बरस बरगद तले
खेत आजा ने खरीदे
अन्न अब तक खा रही हूँ
इसलिये मैं गा रही हूँ।
एक कहँरवा ज्यों उठा कि
राग धोबी झूमता
बज नगाड़ा रोपनी का
धान सूरज चूमता
इस अषाढ़ी चंद्रमा से
माँग कजरी ला रही हूँ
इसलिये मैं गा रही हूँ।
चैत से फागुन तलक हैं
धुन ये बारहमासिये
दिल का है ये ही ठिकाना
जानते हैं डाकिये
पत्र गंगा के सहारे
रासी भिजवा रही हूँ
इसलिये मैं गा रही हूँ।

- आकृति विज्ञा 'अर्पण'

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद की लालसा न रखते हुए....

देश की अखंडता के लिए किया कार्य : मुख्यमंत्री

प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. मुखर्जी ने पहली बार अहसास कराया कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू-कश्मीर

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर विकास के नए द्वार खोले

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. मुखर्जी की भाजपा कार्यालय के निकट स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्र के नवनिर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने कभी पद की लालसा नहीं रखी और देश की एकता एवं अखंडता के लिए कार्य किया। राष्ट्रीय एकता को समर्पित डॉ. मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने देश को आंदोलित करते हुए स्वयं का बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महान शिक्षाविद् और हमारे मार्गदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार यह अहसास कराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, देश का मोर मुकुट है। डॉ. मुखर्जी युवाकाल में कुलपति बने और उन्होंने बंगाल के कई आंदोलनों में भाग लेकर नागरिकों को बताया कि देश के विकास में हमारा योगदान किस प्रकार का होना चाहिए। डॉ. मुखर्जी जब केंद्र में आपूर्ति एवं कपड़ा मंत्री बने तो उनका हर निर्णय सराहनीय रहा। मां भारती की सेवा, लोक-कल्याण और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उनका मार्गदर्शन भारत के निर्माण का आधार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को धारा 370 से मुक्ति दिलाई और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पड़ोसी देश को स्पष्ट संदेश दिया। भारत सरकार के इस फैसले के साथ देश में हर वर्ग का व्यक्ति खड़ा था। कश्मीर में 1947 में ही विकास के द्वार खुल जाने चाहिए थे। अब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रेलवे नेटवर्क, पर्यटन और धार्मिक पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर की समृद्धि के लिए कार्य किए हैं।

इस अवसर पर वरिष्ठ सांसद श्री वी. डी. शर्मा, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय, समाजसेवी श्री हितानंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, सर्वश्री रवींद्र यति, राहुल कोठारी सहित जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित थे।

गुना में अंडर ब्रिज में पानी सिलेंडर भरा ट्रक डूबा

शिवपुरी में स्कूल के आवासीय परिसर में जलभराव, एसडीईआरएफ ने टीचर्स समेत 10 को निकाला

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी जिले में भारी बारिश के चलते कोलारस के लुकवासा में ज्ञान स्थली स्कूल के आवासीय परिसर में जलभराव हो गया। वहां फंसे कुछ टीचर्स समेत लोगों को निकालने के एसडीईआरएफ की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा। हॉस्टल से दो बच्चों समेत 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

पार्वती नदी उफान पर

श्योपुर जिले में भारी बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। बड़ौदा के पास कूहंजापुर पुलिया पर पानी ऊपर आने से श्योपुर-बारां हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ से आवाजाही रुकी है। गुना में रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरने से सिलेंडर लोड ट्रक डूब गया। शिवपुरी में एक घर में आकाशीय बिजली गिरने से घर के खिड़कियों में दरारें आ गई। वहीं, अशोकनगर जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जन जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सोमवार सुबह मुंगावली में भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। गुना में भी यही हालात हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) और टर्फ के एक्टिव होने से मध्यप्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। रविवार को पूरे प्रदेश में बारिश हुई। वहीं, उज्जैन में रेड, इंदौर-देवास में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार उज्जैन समेत 4 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उज्जैन, शाजापुर, आगर-मालवा और राजगढ़ में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। नीमच, मंदसौर, इंदौर और देवास में ऑरेंज अलर्ट है।

इंडिगो के 3 अफसरों पर एससी/एसटी एक्ट का केस

गुरुग्राम (एजेंसी)। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एअरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने फ्लाइट के कैप्टन समेत 3 लोगों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। ट्रेनी पायलट ने आरोप लगाया कि उसे भरी मीटिंग में बेइज्जत कर जातिसूचक शब्द कहे गए। जातिसूचक शब्द के साथ कहा गया- यू आर नॉट फिट टू फ्लाई, यू गो बैक एंड स्टिच द स्लीपर्स (तुम प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं हो, वापस जाओ और चप्पलें सिलो)। गुरुग्राम में मीटिंग के बाद ट्रेनी पायलट ने बेंगलुरु में अपने साथ हुई घटना की पुलिस से शिकायत की। कर्नाटक पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर गुरुग्राम भेजी है। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ईरान का खुला ऐलान

न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे

● कहा-अमरीका ने युद्ध की शुरुआत की, खत्म हम करेंगे ● ईरानी सेना ने दी धमकी, जवाब के लिए तैयार रहिएगा

तेहरान (एजेंसी)। ईरान की सेना ने अमेरिका के हमलों का जवाब देने की धमकी दी है। ईरान सैन्य केंद्रीय कमान ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि परमाणु ठिकानों पर हमलों ने युद्ध का मैदान खोल दिया है। आपने शुरुआत की है, तो अब कड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ईरानी सेना के मेजर जनरल अब्दुलरहीम मौसवी ने भी सख्त शब्दों में अमेरिकी

हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इजरायल को रोकने के बजाय हमारे ऊपर हमले किए। ऐसा करते हुए अमेरिका ने ईरान को उसके हितों की रक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई करने का विकल्प दे दिया है। अमेरिकी हमलों पर रिएक्शन देते हुए ईरानी सेना के प्रवक्ता ने वीडियो जारी किया है। इसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति को गैंबलर ट्रंप कहकर संबोधित कर रहे हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने सीधे ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि आपने युद्ध को शुरू किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। प्रवक्ता ने इस वीडियो में अंग्रेजी में अपनी बात कही है।

अमेरिका के बाद इजराइल का ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमला

इजराइल ने ईरान पर अपने ताजा हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना बनाया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह हमला ठीक उसी जगह किया गया, जहां रविवार सुबह अमेरिका ने बस्टर बम गिराए थे। परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले के बीच ईरान ने कहा कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी आलोचना की और इसे 'गंभीर अपराध' बताया। इससे पहले ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने सोमवार को ट्रम्प को सीधे संबोधित करते हुए कहा, गैम्बलर ट्रम्प, आपने युद्ध शुरू जरूर किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे।

पहलगाम हमले में गिरफ्तार आरोपियों ने एक आतंकी को पहचाना

● कश्मीर पुलिस ने इसका स्कैच-फोटो जारी नहीं किया था, दो मददगार हुए थे अरेस्ट

श्रीनगर (एजेंसी)। पहलगाम हमले के तीन आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की गिरफ्त में आए दो आरोपियों ने बताया है कि हमला करने वाले तीन आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी दो पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। सुलेमान भी उसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें वे आतंकी शामिल थे, जिनकी तस्वीर पहलगाम हमले के बाद सामने आई थी। इन आतंकियों में हाशिम मूसा, तल्हा भाई और जुनैद थे। हालांकि, जुनैद पिछले साल ही एनकाउंटर में मार दिया गया था। जुनैद के मोबाइल फोन में ही इन आतंकियों के फोटो मिले थे। उस फोटो में सुलेमान की फोटो भी है।

विधानसभा उपचुनाव में 4-1 से आगे इंडिया

● भाजपा को झटका, केजरी को मिली गुड न्यूज

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती खत्म हो गई है। परिणामों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे दलों ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं भाजपा को सिर्फ गुजरात की कड़ी सीट पर जीत मिली है। अब तक आए परिणामों के अनुसार आम आदमी पार्टी को गुजरात की विसावदर सीट पर जीत मिली है। यहां से उसके कैंडीडेट गोपाल इटालिया जीत गए हैं तो वहीं पंजाब की लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने भी जीत हासिल की है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 41 °c
न्यूनतम 35°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 24 जून 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

अच्छी खबर

कर्नाटक में अपनी सड़कें खुद बना रही है जनता

● बदलाव की लहर, 6 जिलों में 7 जगह रोड तैयार ● सालों से खराब सड़के एक-दो हफ्ते में ही बन रहीं

कोवरकोल्ली (एजेंसी)। कर्नाटक में बदलाव की एक अलग लहर चली है। खराब सड़कों की शिकायत करते-करते थक चुके लोग खुद ही अपने यहां की सड़कें बनाने लगे हैं। इसके लिए वे आपस में चंदा और श्रमदान कर रहे हैं। नतीजा, जिन खराब सड़कों की सालों से सरकार से शिकायत कर रहे थे, वे एक दिन में दुरुस्त हो रही हैं। जैसे चिकमंगलूर जिले के श्रृंगी के पास भारतीयनूर और बनशंकरी के लोगों ने 15.75 लाख

रुपए इकट्ठे कर 286 मीटर लंबी सड़क खुद ही बना डाली। हासन जिले के मत्स्यशाला गांव में एक शख्स ने 4 ट्रक ईंट-पत्थर दान किया। इसके बाद गांव वालों ने चंदा किया और श्रमदान कर सड़क बना दी। गांव के पंडियन डी कहते हैं- हम अपने नेताओं पर शर्मिंदा हैं। राज्य के छह जिलों के सात गांवों में लोगों ने अपने स्तर पर ही सड़कें बना दी हैं। इनमें गडग, धारवाड़, शिवमोग्गा, कोडागु, कोप्पल और हासन जिले शामिल हैं।

इनमें भी सरकारी सिस्टम से परेशान आम लोगों ने खुद ही सड़क बनाने की पहल की है। पीपल्स रोड के संस्थापक स्वप्नील बंडी ने कहा, हम पूरे देश में हर राज्य भर में ऐसी मुहिम चलाना चाहते हैं ताकि सरकारी सिस्टम को ठोस जिम्मेदारी का अहसास हो सके। अब तक 286 गांवों ने हमसे संपर्क किया है। कोप्पल में डेढ़ किलोमीटर सड़क बना दी है।

युद्ध के मैदान में 'मच्छर' उतारेगा चीन करेगा बड़ा खेला

बीजिंग (एजेंसी)। चीन समय के साथ-साथ खुद को सशक्त बनाने में लगा हुआ है। इसी तरफ चीन ने एक ओर कदम बढ़ाया है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक मिलिट्री ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन का साइज और आकार मच्छर जैसा है। मच्छर के साइज वाला यह ड्रोन युद्ध के मैदान में

तबाही मचाने के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इसका यूज करके न सिर्फ सर्विलांस किया जा सकता है। बल्कि इसका यूज टोही मिशन को अंजाम देने के लिए भी कर सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के वैज्ञानिकों ने मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मच्छर के आकार का एक बहुत छोटा ड्रोन डेवलप किया है।

हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा टला

परिजन खुद स्ट्रेचर पर मरीज को 11वीं मंजिल तक ले गया, ढलान पर बिगड़ा संतुलन

भोपाल (नप्र)। हमीदिया अस्पताल से एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है। इसमें एक हृदय रोगी को उसका अकेला परिजन स्ट्रेचर पर धक्का देता हुआ पुरानी कैथलैब से नए भवन की 11वीं मंजिल तक ले जाता दिख रहा है। रास्ते में अमृत फार्मेसी के पास ढलान पर परिजन का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मरीज को गिरने से बचा लिया। समय रहते संभल जाने से बड़ा हादसा टल गया। वीडियो से अस्पताल में स्टाफ की कमी और सुरक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर हो रही हैं।

प्रबंधन के दावों की खुली पोल- यह स्थिति तब है जब अस्पताल प्रबंधन ने पुरानी कैथलैब से वार्ड तक मरीजों को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा देने का दावा किया था। लेकिन, हकीकत में न तो एम्बुलेंस मिल रही है और न ही मरीजों को ले जाने के लिए कोई सपोर्ट स्टाफ। यह समस्या किसी एक मरीज की नहीं, बल्कि हर महीने कैथलैब में प्रोसीजर के लिए आने वाले 300 से 400 हृदय रोगियों की है।

धूप-बारिश में स्ट्रेचर पर मरीज- फिलहाल पुरानी कैथलैब ट्रॉमा बिल्डिंग के पीछे चल रही है। इसके सामने का जर्जर भवन तोड़ा जा रहा है। प्रोसीजर के बाद मरीजों को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर परिजन धक्का देकर पुरानी कैथलैब से पुरानी फार्मेसी तक चढ़ाई पार कराते हैं। इसके बाद अमृत फार्मेसी और फिर नए भवन तक ले जाना होता है। बीच में एक सीधी ढलान भी है, जो बारिश में फिसलन भरी हो जाती है। इससे हादसे का खतरा बना रहता है। करीब आधा किलोमीटर के इस रास्ते में एक ओर निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे भारी वाहन आते-जाते रहते हैं।पूरे रास्ते में धूप और बारिश से बचने का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी होती है।

कांग्रेस नेता ने हॉस्पिटल में घुसकर स्टाफ को पीटा, एफआईआर

डॉक्टर पर आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी पेशेंट से पैसे लेने का आरोप

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के हार्ट इनफिनिटी हॉस्पिटल में कांग्रेस नेता और हॉस्पिटल स्टाफ में मारपीट का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने ओमती थाने में शिकायत की। इसमें

बताया कि डॉक्टरों पर हमला किया गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता विजय रजक पर एफआईआर दर्ज कर ली।

इधर, कांग्रेस नेता विजय रजक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी से शिकायत की है। इसमें कहा कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इनफिनिटी अस्पताल के संचालक ने रुपए लिए हैं। शुक्रवार को हुए विवाद का वीडियो रविवार को सामने आया।

डॉक्टर बोले- 5 मिनट में डिसीजन लो

दरअसल, 14 जून 2025 को पनागर निवासी एक मरीज विष्णु प्रसाद को सीने में दर्द की शिकायत के चलते उसे तैयब अली चौक पर स्थित हार्ट इनफिनिटी हॉस्पिटल लाया गया।प्रारंभिक जांच के बाद मरीज को बताया कि हार्ट में ब्लाकेज हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की टीम ने कहा कि आपको सिर्फ 5 मिनट में डिसीजन लेना है कि इलाज करवाना है या नहीं।

इस पर आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन करने की बात कही। तब संचालक डॉ. अंकित अग्रवाल के चेंबर से उनका एक असिस्टेंट बाहर आया। कहने लगा कि आयुष्मान योजना के बाद भी 20 हजार रुपए अतिरिक्त लगेंगे। विरोध करने के बाद डॉक्टर निःशुल्क ऑपरेशन को तैयार हो गए।

कामाख्या मंदिर में शुरू हुआ अंबुबाची मेला, 'मासिक धर्म' से है रिश्ता

● तीन दिन तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, मासिक धर्म में होती हैं माता

दिसपुर (एजेंसी)। असम का कामाख्या मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है, यहां माता के दर्शन करने के लिए भक्त हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। और ये गिनती तब और बढ़ जाती है, जब यहां 3 दिन के लिए अंबुबाची मेला लगता है। ये मेला भारत के सबसे खास और लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दौरान लोग इकट्ठा होते हैं और असम की कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेते हैं। ये पूरा त्योहार कामाख्या मां की रजस्वला स्थिति अर्थात मासिक धर्म के इर्द-गिर्द घूमता है। जहां भारत के कई हिस्सों में आज भी पीरियड्स को लेकर चुप्पी, शर्म और पाबंदियां देखने को मिलती हैं, वहीं असम में इसे सम्मान के साथ पूजा जाता है। इस मेले के दौरान देवी की मासिक धर्म की अवस्था को पूजते हैं। गुवाहाटी, असम की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर देवी शक्ति और

आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत ही पवित्र और खास स्थान है। मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और दुनियाभर से लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। यहां का सबसे बड़ा त्योहार अंबुबाची मेला है, जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म (पीरियड्स) से जुड़ी एक अनोखी और पुरानी परंपरा के साथ कनेक्टेड है। साल 2025 में ये मेला 26 जून तक मनाया जाएगा।

जल गंगा संवर्धन अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जल क्रांति

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को मजबूती देने के साथ ही प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण की दिशा में देश भर में चलाए जा रहे अभियान को मध्यप्रदेश सरकार मिशन के रूप में चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल क्रांति हो रही है। इस क्रांति के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा खेत तालाब, अमृत सरोवर, डगवेल रिचार्ज बनाए जा रहे हैं। इन कार्यों से प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, साथ ही भू-जल स्तर में भी सुधार होगा और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा परिषद द्वारा जनवरी-फरवरी माह में ही शुरू कर दी गई थी तैयारी, प्लानर सॉफ्टवेयर से बनाई कार्ययोजना-बारिश के पानी का संचयन बड़े स्तर पर किया जा सके, इसके लिए मनरेगा परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू होने के तीन माह पहले जनवरी से ही तैयारी प्रारंभ कर दी गई थी। इसके लिए परिषद द्वारा प्लानर सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया जिसमें कम से कम प्रविष्टि करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत लिए जाने वाले नवीन कार्यों को इस प्लान में शामिल किया गया। इसके अलावा पिछले वर्ष के प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिए उन कार्यों को भी कार्ययोजना में जोड़ा गया गया। प्लानर सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य था मनरेगा के उद्देश्यों एवं प्रावधानों का पालन कराते हुए कार्ययोजना को आसान तरीके से बनाया जाना। परिषद द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराई। खास बात यह रही कि मध्यप्रदेश इस तरह का नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य भी है।

सिपरी साफ्टवेयर से किया स्थल का चयन- तकनीक के साथ बारिश के पानी को संचय किया जा सके, साथ ही नई जल संरचनाओं के निर्माण के लिए स्थल चयन में भी आसानी हो, इसके लिए मनरेगा परिषद द्वारा सिपरी सॉफ्टवेयर बनाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सौजन्य भेंट की।

कैदियों के लड़ते ही ऐक्टिव हो जाएगा लॉकिंग सिस्टम

दिल्ली में तिहाड़ से भी हाईटेक जेल,जल्द शुरू होने वाला है काम

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के नरेला में एक नई हाई-सिक्योरिटी जेल बनने वाली है। यह जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल से प्रेरित है। इस जेल को बनाने का काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 148.6 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारियों का कहना है कि पहले टेंडर में कोई ठेकेदार नहीं मिला था। इसलिए नियमों में बदलाव किया गया और वित्तीय पहलुओं पर फिर से काम किया गया। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव (प्रिजन्स) को भेजा गया। यह नई जेल दिल्ली की अन्य जेलों, जैसे तिहाड़, मंडोली और रोहिणी का बोझ कम करेगी। इन जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि विभाग जल्द ही 11 एकड़ के प्लॉट पर जेल का पहला चरण शुरू करेगा। दूसरे चरण में, कर्मचारियों के रहने के लिए घर और एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। नई जेल में 250 सेल होंगे। ये सेल एक केंद्रीय वॉचटावर से इस तरह निकलेंगे कि पूरी जेल एक पहिये के स्पोक्स की तरह दिखेगी।

एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगे कैदी

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि नरेला की जेल में एक लॉकिंग सिस्टम होगा, जो जेल में दंगे या झड़प होने पर अपने आप शुरू हो जाएगा। गार्डों को बॉडी कैमरे भी दिए जाएंगे। सेल इस तरह से बनाए जाएंगे कि हाई-रिस्क कैदियों को एक-दूसरे को देखने या बात करने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे जेल में गैंग बनाने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी। जेल में इन-बिल्ट जैमर लगाए जाएंगे, जिससे मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जेल कर्मचारियों और कैदियों के परिवारों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जेल की दीवारें बहुत ऊंची होंगी ताकि कोई फोन, ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित चीजें अंदर न फेंक सके।

पांच लोग कर रहे हैं सब खेल, मेरी जान को खतरा

कोर्ट जाएंगे..तेज प्रताप यादव का ऐलान-ए-जंग

पटना (एजेंसी)। बिहार के पूर्व मंत्री और निलंबित राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। तेज प्रताप यादव ने कहा- 'अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारे दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं... मेरी जान को खतरा है।' तेज प्रताप यादव ने कहा-जिस तरीके से प्रकरण हुआ, किन लोगों के माध्यम से साजिश करके मुझे पार्टी से निकाला गया, ये बिहार की पूरी जनता ने देखा। पूरी जनता मेरा स्वभाव जानती है, इसी का गलत फायदा उठाकर मुझे कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की। तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। मैं कुछ लोग जो वहां बैठे हैं उन्हें चुनौती देता हूं। मैं अब जनता के बीच जाऊंगा, जनता न्याय करेगी।

भारत में सस्ते दामों पर मक्का-सोयाबीन बेचने पर अड़ा अमेरिका

इससे भारतीय किसानों को नुकसान,भारत-अमेरिका ट्रेड डील बीच में अटकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील, कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बीच में अटक गई है। ट्रेड डील के लिए अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ये प्रोडक्ट भारत में सस्ते बिक सकेंगे। वहीं भारत सरकार किसानों को नुकसान होने के कारण इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाना चाहती। भारतीय अधिकारीयों का मामना है कि अगर अमेरिकी सस्ते फूड भारत में आ जाएंगे, तो भारतीय किसानों की फसलें बिकना मुश्किल हो जाएगी।

ऐसे में डील पर असमंजस बना हुआ है। 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले इसका हल निकलना मुश्किल लग रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत फसलों (मक्का, सोयाबीन) और अन्य कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। साथ ही, वो मेडिकल डिवाइसेज पर टैरिफ और डेटा लोकलाइजेशन नियमों में ढील चाहता है। अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों, गाड़ियों, और व्हिस्की जैसे सामानों के लिए भी कम शुल्क की मांग कर रहा है। भारत ने अमेरिका की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, खासकर कृषि और डेयरी बाजार खोलने की मांग को। भारत का कहना है कि इससे लाखों गरीब किसानों को नुकसान होगा। भारतीय उत्पाद, अमेरिकी उत्पादों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारत ने

कहा है कि अगर अमेरिका ने स्टील और ऑटोमोबाइल पर शुल्क लगाए, तो हम भी जवाबी शुल्क लगाएंगे। भारत चाहता है कि अमेरिका उसके टेक्सटाइल, चमड़ा, दवाइयां, और ऑटो पार्ट्स पर शुल्क हटाए या कम करे। भारत ने शुरू में शून्य शुल्क की मांग की थी, लेकिन अब कम से कम 10 फीसदी बेसलाइन टैरिफ पर सहमति की उम्मीद है, जो अमेरिका सभी देशों पर लागू कर रहा है। अगर 9 जुलाई तक कोई डील नहीं हुई, तो अमेरिका भारत के सामान पर 26 फीसदी शुल्क लगा सकता है, जिसमें टेक्सटाइल, दवाइयां, और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा। भारत भी जवाब में अमेरिकी सामान पर शुल्क बढ़ा सकता है, जिससे व्यापार तनाव बढ़ सकता है। बातचीत अभी चल रही है। जून 2025 में दिल्ली में हुई चर्चाओं में डिजिटल ट्रेड और कस्टम्स सुविधा जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। भारत कुछ कृषि उत्पादों और गाड़ियों पर शुल्क कम करने पर विचार कर रहा है, बशर्ते अमेरिका भारत के टेक्सटाइल और जूते जैसे सामानों पर 10 फीसदी शुल्क दे लेकिन जीएम फूड और डेयरी जैसे मुद्दों पर रुकावट बनी हुई है। भारत और अमेरिका दोनों डील को जल्दी फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन भारत किसानों को लेकर चिंतित है।

राहुल गांधी ने कहा-आदिवासी भारत के पहले मालिक

दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष की आदिवासी नेताओं के साथ मीटिंग, राहुल बोले-आदिवासी नेतृत्व तैयार करें

भोपाल (नप्र)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 राज्यों के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की। इनमें आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, सीईसी मेंबर ओंकार सिंह मरकाम, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, विधायक सुनील उईके, खरगोन के लोकसभा प्रत्याशी रहे पोरलाल खर्ते, धार के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल मौजूद थे।

आदिवासी वर्ग में नेतृत्व तैयार करने का काम करें- 10 जनपथ, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं के साथ संवाद के दौरान कहा- आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं। उनकी पीड़ा, समस्याओं और संघर्षों को समझ कर, उनके जल, जंगल, जमीन और अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा समर्पित हूं।

बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी वर्ग में नेतृत्व तैयार करने का काम करें। जो आदिवासी युवा अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। सामाजिक रूप से जो मुखर

होकर आदिवासी समुदाय के मुद्दे उठाते हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आदिवासी वर्ग के पढ़े-लिखे युवाओं को भी पार्टी से जोड़ने पर काम करें। आदिवासी वर्ग में नया नेतृत्व तैयार करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए।

सामाजिक संगठनों के बजाय, आदिवासी कांग्रेस को महत्व मिले- बैठक में शामिल हुए धार के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने राहुल गांधी से कहा- विभिन्न सामाजिक संगठन अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। हम उनके दबाव में कुछ लोगों को चुनाव में टिकट दे देते हैं। सामाजिक संगठनों के लोग पार्टी पर टिकट देने का दबाव बनाने लगते हैं। इससे पार्टी के साथ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता निराश होते हैं। हमें सामाजिक संगठनों के बजाय आदिवासी कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनाव में प्राथमिकता देना चाहिए। मुवेल ने आगे कहा- आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के सुझावों को टिकट वितरण में महत्व मिलना चाहिए। इससे आदिवासी कांग्रेस मजबूत होगी और पार्टी को फायदा मिलेगा।

राहुल ने कहा- आदिवासियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए- बैठक में राहुल गांधी ने कहा- विस्थापन, पेसा कानून के क्रियान्वयन में गड़बड़ी, वनाधिकार जैसे आदिवासियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी नेताओं से अपने-अपने राज्य के आदिवासियों की मुख्य समस्याओं और उनके समाधान को लेकर भी सुझाव मांगे।

प्राणे जलम्-लय और ताल का मधुर संगम

सदानीरा- भारत भवन के अंतरंग सभागार में प्रस्तुति

भोपाल। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत सदानीरा समागम के तीसरे दिन भारत भवन के अंतरंग सभागार में प्रख्यात नृत्यांगना गीता चंद्रन द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका प्राणे जलम् की प्रस्तुति हुई। यह नृत्य संयोजन जल को मात्र एक भौतिक तत्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखने का आह्वान करता हुआ दिखाई दिया। इसमें तालों के माध्यम से जल की प्रवाहशीलता और लयात्मकता का सजीव चित्रण मुखरित हुआ तथा कविताओं के माध्यम से जल को स्त्री-भावना के रूपक के रूप

में चित्रित किया गया। जहाँ उसकी तरलता स्त्री की करुणा, संघर्ष और शक्ति को प्रतिबिंबित करती है। नृत्य को एक संवेदनशील माध्यम बनाकर जल की कल्पना को भावनाओं और प्रतीकों में ढाला गया। इस नृत्य संयोजन में 'संगम अलारिप्पु' खंड में प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेले को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियाँ संगम स्थल पर मिलती हैं। तीन भिन्न तालों के माध्यम से इन तीनों नदियों की विशिष्टता को दर्शाया गया, जो अंततः एक लयबद्ध समता में विलीन होकर एकता का प्रतीक बन जाती हैं। कालिदास कृत 'ऋतुसंहार' से प्रेरित खंड में वर्षा ऋतु की बूंदों से धाराओं और नदियों के निर्माण की प्रक्रिया को नृत्यात्मक रूप में उकेरा। यह प्रस्तुति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या आज के मानवीय अस्तित्व की जटिलताओं का प्रतीक जल बन सकता है? प्राणे-जलम् एक आह्वान है उन पवित्र जलों की स्मृति का जो जीवन का स्रोत हैं, जो चेतना को प्रवाहित करते हैं, और जो समस्त मानवता को दिशा और शक्ति प्रदान करते हैं।

बाढ़ से निपटने भोपाल के जोन में भी कंट्रोल रूम

महापौर ने निरीक्षण किया; पूछा-रविवार को हुई बारिश से कितनी शिकायतें आईं?

भोपाल (नप्र)। लगातार बारिश होने से भोपाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। पिछले कई साल से दामखेड़ा, समरधा, अशोका गार्डन, शिवनगर, बाणगंगा चौराहा, करोंद, कोलार समेत कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। इस बार ऐसे हालात न बने, इसलिए निगम ने मुख्य कंट्रोल के अलावा सभी 21 जोन में भी कंट्रोल बनाए हैं। ताकि, बाढ़ की जानकारी मिलते ही बचाव कार्य शुरू किए जा सके। इससे पहले सोमवार सुबह महापौर मालती राय निगम के मुख्य कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान कुछ

कर्मचारी गायब मिले। जिन पर कार्रवाई करने की बात कही है। महापौर ने बताया, आपदा प्रबंधन को लेकर कंट्रोल रूम पर बारी-बारी से अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो कर्मचारी कंट्रोल रूम पर नहीं मिले, उन पर कार्रवाई करेंगे।

शिकायतों के बारे में जानकारी ली

महापौर राय ने कंट्रोल रूम पर तैनात कर्मचारियों से शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली। खासकर रविवार को हुई शिकायतों के पूछा। इनका कितनी देर में निराकरण किया गया। ये भी जानकारी ली गई।

वक्फ परिसर में कफन में लिपटे मुर्दे और सांकेतिक कब्रें

मुस्लिम समाज का अनोखा प्रदर्शन, अकबरपुर बंजारी में गोशाला भूमिपूजन पर विवाद

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार क्षेत्र के अकबरपुर बंजारी स्थित वक्फ की पंजीकृत कब्रिस्तान जमीन पर गोशाला भूमि पूजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने सोमवार को वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक कब्रें बनाई, कफन ओढ़े लोग मुर्दा बनकर जमीन पर लेटे और सवाल पूछा- अगर कब्रिस्तान पर मॉल और गोशालाएं बनेंगी, तो हम अपने मरे हुओं को कहां दफनाएंगे? प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के संरक्षक शमसुल हसन ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कभी 189 पंजीकृत कब्रिस्तान थे, लेकिन आज सिर्फ 22 बचे हैं। कब्रिस्तान की ज़मीनों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। कोलार में तो कांग्रेस नेताओं ने वक्फ जमीन पर कब्जा कर भाजपा विधायक से भूमिपूजन भी करवा लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो कमेटी हाईकोर्ट का रुख करेगी।

यह हमारी मिट्टी नहीं, हमारी विरासत पर हमला है- समिति ने प्रदर्शन के दौरान वक्फ बोर्ड को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि अकबरपुर के कोलार कब्रिस्तान की 0.620 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

यहां भूमाफिया निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं। यह सिर्फ जमीन का मसला नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय की आस्था, पहचान और बुजुर्गों के सम्मान पर सीधा हमला है।

कब्जा हटाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई हो- वक्फ की संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने की व्यापक मुहिम शुरू की जाए।
इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और नेताओं पर एफआईआर हो।
प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक कब्रें बनाई, कफन ओढ़े लोग मुर्दा बनकर जमीन पर लेटे।

वक्फ बोर्ड ने कहा-

मामला संज्ञान में है- वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने कहा कि मामला संज्ञान में है। हमने अधिकारियों को रिकॉर्ड खंगालने और जमीन की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। यदि जमीन वक्फ की निकली, तो उसकी सुरक्षा के लिए शासन को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी को वापस बुलाने किया बच्चे का अपहरण

भोपाल (नप्र)। भोपाल में पत्नी को वापस बुलाने के लिए एक युवक ने साढ़े तीन साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। मामा ससुर बच्चे को लेकर आरोपी कई जगह घूमता रहा। बच्चे की मां को फोन कर धमकी देता रहा कि अगर पत्नी वापस नहीं आई तो बच्चे को जान से मार दूंगा।
कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित सबरी नगर की 12 नंबर मल्टी से अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने 18 घंटे की मशक्कत के बाद नादरा बस स्टैंड के पास एक होटल से बरामद कर लिया है। आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कमला नगर पुलिस के मुताबिक, किरण रजक (37) पति बल्लू रजक, सबरी नगर में रहती हैं। वह ड्राई क्लीनिंग का काम करती हैं। शुक्रवार देर रात किरण के घर पर उनकी ननद का दामाद गोलू रजक (25), निवासी इंद्रा नगर, हबीबगंज पहुंचा। रात 3.30 बजे उसने दरवाजा खटखटाया। इस दौरान साढ़े तीन साल का विहान बाहर आया तो गोलू ने उसे बहला-फुसलाकर बाहर निकाला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था और बच्चा गायब था। कुछ ही देर में किरण के पास गोलू का फोन आया। उसने कहा- मेरी बीवी किसी और के साथ चली गई है। उसे वापस बुलाओ, वर्ना तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा।

ईरान में फंसा भोपाल का युवक, लौटने से इनकार

- **मां बोली- पीएम मोदी ईरान का साथ दें; डॉक्टरेट करने गई गुलअफशां भी आना नहीं चाहती**

भोपाल (नप्र)। मेरा बेटा कहता है, इतने सालों से ईरान का नमक खाया है। अब जंग के बीच वहां से चला आया तो लोग कहेंगे की डर के भाग गया। इसलिए अब पढ़ाई पूरी करने के बाद ही भारत वापस लौटूंगा। 30 वर्षीय अबरार की मां शाहनूर (50) जब ये कह

रही थीं तो उनके चेहरे पर चिंता और गर्व दोनों के भाव थे। अबरार और उसका परिवार भोपाल का रहने वाला है, लेकिन चार साल पहले पढ़ाई के लिए अबरार अपने परिवार से दूर ईरान चला गया। वहां मासूमा कुम में वो मौलाना बनने की पढ़ाई कर रहा था कि तभी इजराइल-ईरान युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में वहां रह रहे सभी भारतीय छात्र भारत लौटने के लिए बेताब थे, लेकिन अबरार ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। वहीं, दूसरी ओर भोपाल की ही गुलअफशां की कहानी अलग है। वह भी ईरान-इजराइल युद्ध के कारण ईरान में हैं। वो भारत आना चाहती हैं, लेकिन युद्ध के कारण ये मुमकिन नहीं हो पा रहा।

सरकार से अपील- ईरान का आप भी साथ दो

अबरार की मां भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से कहती हैं कि मोदी इस झगड़े-लफड़े के बीच में पड़कर इसको सुधारें, गलत चीज को मना करें। ईरान हक का साथ दे रहा, आप भी उसका साथ दो। अगर सब ईरान की तरफ हो जाएं तो, इजराइल चुपचाप बैठ जाएगा। इजराइल फिलिस्तीन, गाजा पर जुल्म कर रहा है। उन्हें जला रहा है, मिटा रहा है। सबकी जमीन हड़प रहा है। ईरान ने आवाज उठाई, तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा। ईरान खुद अकेले कामयाब होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग, नए तबादले किए, पुराने अफसर हटाए नहीं

भोपाल (नप्र)। मप्र में तबादलों का मौसम चल रहा है। सभी विभागों में धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। तबादलों की लिस्ट को लेकर बीजेपी के विधायक और संगठन के लोग कई जिलों में नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं, तबादलों में भी कई गड़बड़ियां देखने को मिल रहीं हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में हुए तबादलों के बाद एक ही जगह पर दो-दो अफसर पहुंच गए हैं। करीब दर्जन भर ऐसे तबादला आदेश जारी हो चुके हैं। इनमें नए अफसर की पोस्टिंग हो गई लेकिन, पहले से पदस्थ अफसर को दूसरी जगह नहीं भेजा गया है।

विधायक ने कहा- कोई नाराजगी नहीं

चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा पेंची ने तबादलों को लेकर लिखे गए पत्र पर भोपाल में मीडिया से कहा,कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूं और भाजपा में सभी मिलकर काम करते हैं। भाजपा एक परिवार है। जब कोई छोटी-छोटी चीजें या समस्याएं हमारे संज्ञान में आती हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उन्हें संबंधित स्तर पर रखते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन विपक्षियों का काम है कि वे ऐसी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करें। वे कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते, लेकिन जब हम काम करते हैं, तो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं कि कैसे हमें घेरा जाए। हमारा हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर न्याय के लिए काम कर रहा है। हमने अपनी बात रखी, जिसे सबने संज्ञान में लिया और पूरी मदद भी मिली। भाजपा हर कार्यकर्ता और हर गरीब का ध्यान रखती है।

गड़बड़ी का नमूना समझिए- ग्वालियर संभाग 1 के डिप्टी कमिश्नर परमानंद सौंधिया को ग्वालियर वृत्त 3 में भेजा गया है। ग्वालियर वृत्त 3 के डिप्टी कमिश्नर हरिदास भालेकर को सागर वृत्त कार्यालय भेजा गया है। वहीं, सागर वृत्त के डिप्टी कमिश्नर निर्मल परिहार को भोपाल वृत्त 5 भेजा गया है। लेकिन, चौंकाने वाली बात ये है कि भोपाल वृत्त 5 में पहले से पदस्थ डिप्टी कमिश्नर मिथलेश वामनकर को कहीं नहीं भेजा गया है।

न्यूजीलैंड में बाबा बागेश्वर से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री डेविड ब्रीन

धीरेंद्र शास्त्री ने सुनाई हनुमान जी की कथा, कहा- यहां कुछ लोगों ने आस्था को ठेस पहुंचाई

खजुराहो (नप्र)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री 17 दिन के विदेश दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया और फिजी में तीन दिनों की हनुमंत कथा के बाद वे न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। यहां ऑकलैंड में उनकी कथा चल रही है।

ऑकलैंड में धीरेंद्र शास्त्री की कथा सुनने न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री डेविड ब्रीन सीमोर पहुंचे। उन्होंने कथा से पहले मंच से भारतीय समुदाय के साथ राष्ट्रगान गाया। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी पुस्तक भेंट की। डेविड ब्रीन ने कथा के मंच से उपस्थिक लोगों को संबोधित करते हुए धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ की। इस दौरान अध्यात्म और विश्व शांति के साथ ही भारत-न्यूजीलैंड के परस्पर संबंधों पर चर्चा हुई। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की सांसद परमजीत परमार भी मौजूद थीं। कथा के पहले धीरेंद्र शास्त्री ने व्यास पीठ से कहा...आज की कथा

सम्पूर्ण विश्व मे शांति हो, थर्ड वर्ल्ड वार से दुनिया बचे, इसके लिए समर्पित होगी। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं इस देश में शांति बनी रहे। देश मे मनुष्यों में एकता रहे। न्यूजीलैंड और भारत का प्रेम सदा बने रहे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में कुछ दिन पहले विचित्र मानसिकता के लोगों ने किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। हम आज की कथा में हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में संस्कृति धर्म की शांति बनी रहे। इस देश में मनुष्यों में एकता बनी रहे और यहां सनातन का अभिप्राय जगमगाता रहे। न्यूजीलैंड और भारत का प्रेम यूं ही बना रहे।

विश्व शांति के लिए प्रार्थना, हवन किया- धीरेंद्र शास्त्री न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे तो वहां रहने बाले ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा उनका मंत्रोच्चारण के साथ विशेष स्वागत किया गया। शास्त्री ने विश्व शांति, कल्याण और मानव कल्याण के लिए हवन भी किया।

भोपाल में शोभायात्रा के बीच युवक का मर्डर

नाचते समय हुआ विवाद, हमीदिया पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय-कहा रैली में हथियार कैसे पहुंचे?

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में रविवार रात धार्मिक शोभायात्रा के दौरान हुए हिंसक हमले में 20 साल के युवराज बंशकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दो अन्य युवक रोहित सेन और संजू वर्मा पर भी हमला किया गया। यह वारदात युवा हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित शोभायात्रा के दौरान हुई। शोभायात्रा सिंधी कॉलोनी से शुरू होकर माता मंदिर चौराहे तक निकाली जा रही थी। यात्रा में डीजे पर युवाओं के नाचने के दौरान अचानक कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। अफरातफरी में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से युवराज की मौत हो गई। मृतक युवराज बंशकार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला था और इन दिनों भोपाल में अपने परिजनों के साथ रह रहा था। हमीदिया अस्पताल में उसका पोस्टमॉर्टम किया गया।

पूर्व सीएम पहुंचे हॉस्पिटल, एसीपी से पूछा- हथियार कहां से आए- घटना के बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हमीदिया अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया और कानून-व्यवस्था

पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय ने एसीपी राकेश बघेल से पूछा कि शोभायात्रा में हथियार कैसे पहुंचे, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि जुलूसों में हथियार नहीं ले जाए जा सकते। उन्होंने कहा- मेरे पास वीडियो है, जिसमें लोग हथियार लेकर चल रहे हैं। क्या आप एक्शन लेंगे? इस पर एसीपी ने जवाब दिया- 101 प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी।

युवक बोला- यात्रा में नाचने के बीच हुआ विवाद- घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने इब्राहीमगंज निवासी पीयूष सोनी का नाम सामने रखा है, जो कथित रूप से हमलावरों में शामिल था। पुलिस ने पीयूष समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक युवराज के साथी संजू ने बताया, रामजी की रैली थी, जिसमें हम शामिल हुए थे। इस बीच हम नाचने लगे। तभी किसी और ने पीयूष को धक्का दे दिया, लेकिन उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। जब हम वहां से जाने लगे, तो वह अपने गैंग के साथ वापस आया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। इसी दौरान युवराज की मौत हो गई।

पुलिस कह रही है- शोभायात्रा के बाद हुई वारदात- हनुमानगंज थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि यह हमला शोभायात्रा समाप्त होने के बाद हुआ।

'जल गंगा संवर्धन अभियान' का समापन

हर जिले में होंगे 24 से 30 जून तक विशेष आयोजन

भोपाल(नप्र)। प्रदेश में जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जनजागरूकता को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' का 30 जून 2025 को समापन होगा। उल्लेखनीय है कि अभियान 30 मार्च से पूरे प्रदेश में शासन और समाज के सहयोग से चलाया गया था। सभी जिलों में 24 से 30 जून तक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समापन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर्स एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस समापन सप्ताह का उद्देश्य अभियान की उपलब्धियों और इसके जरिए हुए कार्यों के लाभों को जन-जन तक पहुँचाना है। साथ ही नागरिकों से मिले सुझावों के आधार पर भविष्य की नीतियों में सुधार करना और जनप्रतिनिधियों, जलदूतों व स्थानीय नागरिकों को आगे की योजनाओं में सहभागी बनाना भी इसका अहम हिस्सा है। समापन सप्ताह के दौरान कई गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी इनमें अभियान के दौरान हुए कार्यों और जनसहभागिता पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जनप्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख लोगों के साथ क्षेत्र का दौरा कर किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा।

संपादकीय

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट ?

अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले और इजराइल के पक्ष में खुलकर सामने आने के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की घंटी तेज हो गई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन यदि ईरान के पक्ष में रूस और चीन अपनी सेना के साथ आ गए तो जरूर विश्व युद्ध की आशंका सच्चाई में बदल जाएगी। मध्य पूर्व के भयंकर तनाव का घटनाक्रम जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर समूचा विश्व चिंतित है। इनमें वो देश जो सीधे इससे जुड़े हैं तो हैं ही, वो भी शामिल हैं, जिनका सीधा सम्बंध नहीं हैं या फिर अब तक तटस्थ बने हुए हैं। यदि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी तो किसी के लिए तटस्थ रहना दूभर हो जाएगा। क्योंकि तब वैश्विक शक्तियों का अलायंस अलग तरीके से होगा। अभी तक अमेरिका द्वारा इजराइल ईरान विवाद में सीधे न कूदने से यह संभावना बनी हुई थी कि विवाद का कोई कूटनीतिक हल निकालने की कोशिश हो सकती है। लेकिन न तो इजराइल के ईरान पर हमले रूक रहे हैं, न ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए राजी है और न ही अमेरिका ईरान को माफ करने को तैयार है। उधर ईरान भी आखिरी दम तक मुकाबले का मन बनाए बैठा है। यानी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैश्विक संगठन भी इस टकराव को रोकने में असमर्थ हैं तो बाकी मुस्लिम देश भी केवल ईरान पर इजराइली हमले पर बयानबाजी भर कर रहे हैं। इन बयानों में उस अमेरिका का कोई जिक्र नहीं है, जिसके दम पर यह सब हो रहा है। अलबत्ता अमेरिकी बी 2 विमानों द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर भीषण बमबारी से इजराइल खुश है। इसका कारण वह राहत है, जो अमेरिका के खुलकर साथ आने के कारण मिली है। वरना इजराइल पर ईरान ने अपनी मिसाइलों जो भयंकर पलटवार शुरू किया था, उससे नन्हां सा इजराइल घबरा गया था। वो बार अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि वो ईरान पर हमला करे। उधर अमेरिका में अभी भी इस को लेकर एकमत नहीं है कि ईरान सच में परमाणु बम बना रहा था। क्योंकि परमाणु बम बनाने की पुष्टि अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण एजेंसी ने भी नहीं की है। खुद ईरान भी यही कहता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम रचनात्मक कार्यों के लिए है। लेकिन अमेरिका व इजराइल को इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अमेरिका का भी इसमें दोहरा रवैया है। एक तरफ वह परमाणु बम बनाने के आरोप में ईरान पर बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ जिस पाकिस्तान के पास 170 एटम बम हैं, उसे गले लगा रहा है। इस बीच ईरान फिर साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल उस पर हमला करता रहेगा, वह कोई बातचीत नहीं करेगा। वैसे इस पूरे प्रकरण में अमेरिका का रोल संदेह से परे नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ देख रहा है। उसने काफी देर बाद ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया भी तो ऐसा कि उन संयंत्रों को मामूली नुकसान ही पहुंचा। कहा जा रहा है कि हमलों की आशंका के चलते ईरान अपना संवर्द्धित यूरेनियम पहले ही दूसरी जगह छिपा दिया था। लेकिन अमेरिकी हमले के खिलाफ रूस और चीन खुलकर ईरान के पक्ष में युद्ध में उतर आए तो स्थिति बहुत खतरनाक होगी। हालांकि ये दोनों देश ईरान के पक्ष में अपनी सेनाएं भी उतारेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। वो ईरान को आर्थिक और सैन्य सहायता ही देते रहेंगे।

असंभव है इन परिवर्तनों को रोक पाना

नजरिया

तनवीर जाफ़री

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इस समय पूरी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बुरी तरह जूझ रही है। विश्व के किसी न किसी कोने से मानवजीवन को संकट में डालने वाले आये दिन कोई न कोई ऐसे समाचार सुनाई देते हैं जो पर्यावरण पर नज़रें रखने वालों को चौंकाने वाले होते हैं। मानवजनित इस समस्या के चलते इसी पृथ्वी के किसी न किसी भूभाग से कोई न कोई दिल दहलाने वाली ख़बरें अक्सर आती रहती हैं। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। कहीं जंगलों में आग लग रही है तो कहीं पहाड़ धंस रहे हैं। कहीं जंगलों में आग लगने के समाचार आते हैं तो कहीं वनक्षेत्र ख़ासकर वर्षावनों के कम होने की ख़बरें सुनाई देती हैं। कहीं पहाड़, शुष्क रेगिस्तान की तरह होते जा रहे हैं तो कहीं रेगिस्तान में बारिश होने लगी है। कहीं नदियाँ सूख रही हैं तो कहीं बाढ़ तबाही मचाये रहती है। कहीं पहाड़ों की ऊंचाई कम हो रही है तो कहीं करोड़ों वर्षों से बर्फ़ के आवरण से ढके पहाड़ों से बर्फ़ की सफ़ेद चादर हट चुकी है। ज़ाहिर है दुनिया में बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण ही जलवायु परिवर्तन व व ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है। और यही ग्लोबल वार्मिंग और इसके कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले मानव रुपी प्राणी की ही देन है।

इन समस्याओं से जूझने के लिये स्वयं को विश्व के ज़िम्मेदार समझने वाले नेता व शासकगण वातनुकूलित वातावरण में दुनिया में कहीं न कहीं इकठ्ठा होते रहते हैं और पृथ्वी के इन दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हालात पर चिंता व्यक्त करने की औपचारिकता पूरी करते दिखाई देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तो 53 वर्ष पूर्व यानी वर्ष 1972 में ही पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा,संरक्षण तथा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाने की घोषणा भी कर दी थी। तभी से दुनिया के देश इस विषय पर किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिंता करते नज़र आते हैं। इसके लिए विश्व स्तर पर कई सम्मेलन और समझौते भी हो चुके हैं और भविष्य में भी प्रस्तावित हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक ऐसा ही प्रमुख मंच है जहां विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क़दम उठाने पर सहमत होने की औपचारिकता पूरी करते दिखाई देते हैं। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन दुनिया के देशों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए एक साथ लाने का प्रयास करते भी नज़र आता है। इस सम्मेलन में शामिल देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की कोशिश करते भी दिखाई देते हैं।

उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत हुआ पेरिस समझौता एक ऐसा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ लाने की कोशिश करता है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। इसी तरह पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जोकि पर्यावरण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गयी थी। इसी तरह कभी दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का एक समूह जी 20 शिखर सम्मेलन भी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का मंच बन जाता है। निकट भविष्य में भी ब्राज़ील के ऐमेज़ॉन क्षेत्र में स्थित बेलेम शहर में 10-21 नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इसी तरह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद,में आयोजित किया जाएगा।

परन्तु इन सभी वैश्विक प्रयासों के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 50 वर्षों से भी अधिक समय से ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाने व जलवायु संरक्षण के नाम पर होने वाले वैश्विक प्रयासों का आख़िर अब तक नतीजा क्या निकला है? सिवाय इसके कि स्वयं को विकसित कहने वाले देश विकास के नाम पर स्वयं को तो ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा ज़िम्मेदार बनने से रोक नहीं पा रहे जबकि अन्य विकाशील व ग़रीब देशों को फ़ंड देकर उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वही देश इस पर नियंत्रण करें? विकासशील देशों से वृक्षारोपण अभियान चलाने की उम्मीद की जाती है जबकि विकसित देश हथियारों की होड़ व गगनचुम्बी इमारतों को बनाने की प्रतिस्पर्धा में जुटे रहते हैं। विकासशील देश नित नये उद्योग,वाहन व यातायात के अन्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहन बनाने में मशग़ूल रहते हैं जबकि अन्य देशों को प्रवचन देते हैं कि ईंधन की खपत करने वाले 10-15 वर्ष पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के क़ानून बनायें ? आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई यात्रा कम से कम करें, कारों का इस्तेमाल न करें या इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें, मांस व डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, घरेलू व औद्योगिक ज़रूरतों में ऊर्जा खपत में कटौती करें, कम से कम ऊर्जा ख़पत वाले उपकरण ख़रीदें, अपने घरों को तापावरोधी बनायें तथा गैस सिस्टम से इलेक्ट्रिक हीट पंपों पर स्विच करें, आदि आदि। यानी जलवायु सम्मेलनों के नाम पर इकठ्ठा होने वाले देशों में भी 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली कहावत चरितार्थ होते दिखाई देती है।

अन्यथा यदि जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के असल ज़िम्मेदार देश विकास के नाम पर बनाई जाने वाली अपनी नीतियों में ईमानदाराना परिवर्तन करते तो 50 वर्षों के प्रयास के बावजूद आज पृथ्वी की स्थिति इसतरह दिन प्रतिदिन बद से बदतर न हो रही होती। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस ब्राज़ील के ऐमेज़ॉन क्षेत्र में नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और जिस ऐमेज़ॉन क्षेत्र के वर्षावन पृथ्वी को लगभग बीस प्रतिशत ऑक्सीजन प्रदान करते थे उसी ऐमेज़ॉन क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर के जंगल कुछ वर्ष पूर्व ही विकास की भेंट चढ़ गये? हिमालय पर्वत की चोटियां जो हमेशा बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े रहती थीं अब उनकी बर्फ़ पिघलने लगी है। अंटार्टिका के ध्रुवीय ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं। परमाणु युद्ध की दस्तस्क आये दिन सुनाई देती है।अमेरिका,रूस व इस्राईल जैसे देश जब देखो तब कहीं न कहीं युद्ध के नाम पर ख़तरनाक बारूदी प्रदूषण फैलाते रहते हैं। और यही देश नेपाल जैसे छोटे देश तक का प्रदूषण स्तर नापते रहते हैं। शायद यही वजह है कि जलवायु सम्मेलन, नेताओं की तफ़रीह व सैर सपाटे की जगह तो बन जाते हैं परन्तु इन समस्याओं का स्थाई तो दूर अस्थाई समाधान भी निकाल नहीं पाते। इन परिस्थितियों को देखते हुये यह कहना ग़लत नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग व इसके कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोक पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है।

रिश्तों का द्वैत : सामाजिक बंधन या व्यक्तिगत आजादी

मुद्दा

अमित कोहली

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, जिसमें दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। पारंपरिक रूप से विवाह को सामाजिक स्थिरता, नैतिकता और पारिवारिक एकता का आधार माना गया है। विवाह के माध्यम से ना केवल संतानोत्पत्ति, बल्कि सामाजिक संरचना को बनाए रखने की कोशिश की जाती रही है। समय के साथ विवाह की परिभाषा और उद्देश्य बदलते गए हैं। आधुनिक समाज में विवाह साथी, मित्र और सहयोगी की खोज का माध्यम बन गया है।

आज विवाह व्यक्तिगत और भावनात्मक आवश्यकताओं से जुड़ गया है। लोग अब उसे केवल सामाजिक मान्यता प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानते, बल्कि एक साथी, मित्र और सहयोगी की खोज के रूप में देखते हैं। विवाह में दो व्यक्ति एक-दूसरे को भावनात्मक और मानसिक संबल प्रदान करते हैं। इसके अलावा, विवाह कानूनी सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति भी प्रदान करता है। कई अधिकार और सुविधाएँ, जैसे संपत्ति का उत्तराधिकार, चिकित्सा निर्णय लेने का अधिकार और कर लाभ विवाह के माध्यम से सुनिश्चित होते हैं। आर्थिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है, क्योंकि कई लोग विवाह को एक साझेदारी के रूप में देखते हैं, जहाँ दोनों व्यक्ति मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं।

आजकल विवाह के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है, लेकिन यह अभी भी समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था बना हुआ है। कुछ लोग इसे एक पारंपरिक बंधन के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक व्यक्तिगत निर्णय मानते हैं। हाल ही में मेघालय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अन्देशा जताया जा रहा है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी नव-विवाहित पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद और विवाह में बढ़ती असहमति बताई जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम और उसके प्रेमी ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

कुछ समय पूर्व मेरठ में एक और भयावह घटना सामने आई थी, जहाँ मुस्कान नामक महिला ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। सौरभ लंदन से मुस्कान का जन्मदिन मनाने आया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने शव के 15 टुकड़े कर उसे सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया। पुलिस ने जब घर में फैली दुर्गंध के कारण जांच शुरू की, तब इस अपराध का खुलासा हुआ।

'लिव-इन' संबंधों को अक्सर पारंपरिक विवाह का स्वतंत्रता और समता आधारित विकल्प माना जाता है। इसे एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जहाँ दो व्यक्ति बिना सामाजिक और कानूनी बंधनों के साथ रह सकते हैं, एक-दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और अपने रिश्ते को बिना बाहरी दबाव के विकसित कर सकते हैं। 'लिव-इन' की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। युवा वर्ग अब विवाह से पहले एक-दूसरे को समझने और रिश्ते की वास्तविकता को परखने के लिए 'लिव-इन' को प्राथमिकता दे रहा है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए भी आकर्षक है, जो विवाह की कानूनी और सामाजिक जटिलताओं से बचना चाहते हैं। इसके अलावा, 'लिव-इन' में सहजीवन की स्वतंत्रता होती है, जहाँ दोनों साथी बिना किसी सामाजिक दबाव के अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं।

हालाँकि, 'लिव-इन' संबंधों को विवाह का आदर्श विकल्प मानना एक भ्रम साबित हो सकता है। हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि 'लिव-इन' में भी वही समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो विवाह में देखी जाती हैं। श्रद्धा वालकर की हत्या इसका एक भयावह उदाहरण है, जहाँ उसके 'लिव-इन' पार्टनर आफताब पूनावाला ने उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े कर कई दिनों तक छिपाए रखा। इसी तरह, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 23 वर्षीय समीक्षा की उसके ही 'लिव-इन' पार्टनर सतीश ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अन्य घटना छिंदवाड़ा में हुई, जहाँ ममता नामक महिला की उसके 'लिव-इन' पार्टनर जुंगी ने निर्मम हत्या कर दी थी।

इन घटनाओं से पता चलता है कि 'लिव-इन' संबंधों में भी भावनात्मक अस्थिरता, अधिकारों की अस्पष्टता और हिंसा की संभावना बनी रहती है। विवाह में पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाएँ तनाव पैदा कर सकती हैं, जबकि 'लिव-इन' में कानूनी अस्पष्टता और सामाजिक अस्वीकृति असुरक्षा को बढ़ा सकती है। जाहिर है, 'लिव-इन' भी विवाह की समस्याओं का समाधान नहीं हैं, बल्कि वे केवल एक अलग रूप में उन्हीं चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं। हाल के वर्षों में इन दोनों व्यवस्थाओं की असफलता और अप्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं।

विवाह, जो कभी सामाजिक स्थिरता और पारिवारिक संरचना का आधार माना जाता था, अब कई लोगों के लिए एक बंधन बन गया है। पारिवारिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएँ और व्यक्तिगत असंतोष विवाह को तनावपूर्ण बना देते हैं। तलाक की बढ़ती दरें और विवाह में होने वाली हिंसा इस संस्था की असफलता को उजागर करती हैं। मेरठ और इंदौर की घटनाएँ दर्शाती हैं कि विवाह में बढ़ते अविश्वास और बाहरी संबंधों के कारण हिंसा तक की नौबत आ सकती है।

दूसरी ओर, 'लिव-इन' संबंधों को विवाह का स्वतंत्र और प्रगतिशील विकल्प माना गया, लेकिन यह भी विवाह की समस्याओं से मुक्त नहीं रहा। श्रद्धा वालकर की हत्या जैसी घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि 'लिव-इन' संबंधों में भी भावनात्मक अस्थिरता, अधिकारों की अस्पष्टता और हिंसा की संभावना बनी रहती है। कानूनी सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति की कमी के कारण 'लिव-इन' संबंधों में असुरक्षा बढ़ती जा रही है।

विवाह और 'लिव-इन' संबंधों की असफलता ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या दो व्यक्तियों का आजीवन साथ रहने का संकल्प उचित भी है? पारंपरिक विवाह सामाजिक स्थिरता और पारिवारिक संरचना को बनाए रखने के लिए विकसित हुआ था, जबकि 'लिव-इन' संबंधों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक माना गया। लेकिन दोनों ही व्यवस्थाएँ भावनात्मक अस्थिरता, अधिकारों की अस्पष्टता और हिंसा से मुक्त नहीं रह सकीं।

समाधान की दिशा में कुछ संभावित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। विवाह या 'लिव-इन' को स्थायी बंधन मानने के बजाय, इसे एक समझौते के रूप में देखा जाए, जहाँ दोनों पक्षों को स्वतंत्रता और सम्मान मिले। इसके अलावा, विवाह और 'लिव-इन' संबंधों में कानूनी सुरक्षा और अधिकारों की स्पष्टता बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या असुरक्षा को रोका जा सके। विवाह और 'लिव-इन' संबंधों की असफलता को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज संबंध के नए मॉडल की खोज करे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा को प्राथमिकता दे। (सप्रेस)

आदिवासियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर धरातल पर काम करने की है जरूरत

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

मध्यप्रदेश के सभी जिलों में कुल 4,321 ऐलोपैथिक सरकारी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 53,322 बिस्तर उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सरकारी अस्पतालों और वहाँ उपलब्ध बिस्तरों के जिलेवार आँकड़े चौंकाने वाले प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के बड़े जिलों में जहाँ पर्याप्त सरकारी अस्पताल और बिस्तरों की संख्या हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या निराशाजनक हैं।

मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों की संख्या नि:संदेह बढ़ी हैऔर बजट भी बढ़ा है। लेकिन इन संसाधनों की जिलेवार तस्वीर देंखे तो वह चौंकाने वाली है। जिन जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत ठीक हैं, वहाँ सरकारी अस्पतालों, डॉक्टरों और बिस्तरों की संख्या की भरमार है। दूसरी ओर आदिवासी, दूरस्थ या पिछड़े क्षेत्र के जिलों को वास्तव में इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ सरकारी संसाधन अत्यन्त सीमित है। बड़े शहरों और आदिवासी जिलों में उपलब्ध सरकारी अस्पताल और बिस्तरों की तुलनात्मक चर्चा करें तो आँकड़े अत्यन्त निराशाजनक है। जहाँ भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में से प्रत्येक में सरकारी अस्पतालों की संख्या 2000 से भी अधिक है। वहीं दूसरी और आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी अस्पतालों की संख्या 300 से भी कम है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल 12 जिले ऐसे हैं, जहाँ एलोपैथिक सरकारी अस्पतालों की संख्या 22 से 39 के बीच है। ये आँकड़े संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते। अलीराजपुर जिले में सबसे कम 22 सरकारी अस्पताल हैं। डिंडोरी में 26, उमरिया में 30, श्योपुर में 29, मंडला में 35, अनुपपुर में 36, हरदा में 34, निवाड़ी में 28, बैतूल में 39, कटनी में 38, बालाघाट में 35 और बुरहानपुर में 32 ही सरकारी अस्पताल उपलब्ध हैं। इन जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर सामुदायिक अस्पताल तक की संख्या अत्यन्त सीमित है। इससे इन क्षेत्रों के आदिवासियों को सहज उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है।

आदिवासी बहुल जिलों में जहाँ अत्यन्त कम सरकारी अस्पताल हैं, वहीं बड़े शहरों वाले जिलों जैसे भोपाल में 116 सरकारी अस्पताल हैं। इन्दौर में 121, जबलपुर में 159, ग्वालियर में 132 और सागर में 148 सरकारी अस्पताल हैं। यह संख्या संतोषप्रद कही जा सकती है। किन्तु इन जिलों की तुलना में आदिवासी बहुल जिलों की संख्या देखें तो स्थिति निराशाजनक है। बड़े शहरों और आदिवासी जिलों में जहाँ सरकारी अस्पतालों की संख्या में तुलनात्मक बहुत ज्यादा अंतर हैं, वहीं इन अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के बीच भी बहुत अंतर है। जैसे - भोपाल जिले में 2,318 सरकारी अस्पताल है। इन्दौर में 2,220, जबलपुर में 2,463, ग्वालियर में 1,958 और सागर जिले में 1,876 बिस्तर उपलब्ध हैं। ये प्रदेश के कुल गिने-चुने जिले हैं, जहाँ बिस्तरों की उपलब्धता चिकित्सा मानकों के नजदीक है।दूसरी ओर आदिवासी बहुल जिलों में बिस्तरों की कम संख्या चौंकाने वाली है। जैसे अलीराजपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में मात्र 312 बिस्तर ही उपलब्ध है। डिंडोरी में 420, श्योपुर में 387, उमरिया में 385, हरदा में 441,मंडला में 468, बुरहानपुर में 476 और झाबुआ में 497 बिस्तर ही उपलब्ध है। इन जिलों में कुल बिस्तरों की संख्या 500 से भी कम है। यह आँकड़े निराशाजनक कहे जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश में जहाँ आदिवासी बहुल जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत निराशाजनक है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी हालत बदहाल है। उदाहरण के लिए केवल एक आदिवासी जिले धार के एक विकासखंड बाग की ही बात करें तो हमें शिक्षा के हालात का सहज ही अंदाजा हो जाता है। बाग विकासखंड के नरवाली सेक्टर में 40 स्कूलों में से 13 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। सहज ही कहा जा सकता है कि इन आदिवासी गाँवों के बच्चे शिक्षा की सुविधा से वंचित किए गए हैं। बाकी के स्कूलों में भी मात्र एक-एक शिक्षक ही हैं। जब किसी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 वीं तक के समस्त विषयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मात्र एक शिक्षक के जिम्मे होती है, तो वह किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है ? यह सोचने वाली गंभीर बात है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक विशेष विजन वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उन्हें प्रदेश की कमान संभाले अभी एक वर्ष से कुछ समय ही अधिक हुआ है। उन्हें चाहिए कि वे प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े जिलों में सरकारी अस्पतालों, बिस्तरों, डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या बढ़ाएं, ताकि आदिवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसी प्रकार प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में जहाँ भी शिक्षकविहीन स्कूल हैं, वहाँ शिक्षकों की तैनाती करें। इसके साथ ही जिन सरकारी स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है, वहाँ कम से कम दो शिक्षकों की नियुक्ति करे, ताकि आदिवासियों के बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त आदिवासी बहुल जिलों के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त भवन और संसाधनों की व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जब बेटी रसीद बन जाए और बेटों की डिग्री दहेज का इनवॉइस

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

लेखक व्यंग्यकार हैं

बात एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ शादी का मतलब अब मंगलसूत्र से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट से तय होता है। वहाँ एक विज्ञापन अख़बार में छपा-शुद्ध कुलीन, सरकारी नौकरीपेशा, दूल्हा बिकाऊ है-सिर्फ़ एक रात की बोली में। कॉलर ट्यून में माँ कहती है, हमारा लड़का कलेक्टर है, रेट देखो और जियो। ऐसा लग रहा था जैसे लड़का नहीं, आईपीएल की टीम हो, जो हर बॉल के साथ महंगी होती जा रही है। उस रविवार को, जब मंदिर में भगवान को भी आरती के लिए भीख मांगनी पड़ी, लड़के के पिता ने बुलाई थी ब्याह की ब्रीफिंग-एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेबल पर खाकी फाइलें, स्टैम्प पेपर, और एक पुरानी डायरी थी जिस पर लिखा था-देवराज एंड संस: वर-विक्रय में विश्वास।

लड़की के पिता जब पहुँचे तो पहले उन्हें टोका गया-कुर्ता सिलवाया है या वही पुराना वाला? फिर पूछा गया-गाड़ी आई नहीं? बेचारे बोले-हमें तो उम्मीद थी रिश्ता संस्कारों से होगा। लड़के के फूफा ने घूरकर कहा-अरे संस्कारों में तो हमारी दाढ़ी झड़ गई, अब सिर्फ़ स्कार्पियो, एसी और एलसीडी की बात कर। इतना सुनते ही लड़की के पिता के कानों से धुआँ और आँखों से पानी निकलने लगा। उन्होंने कहा, बेटी बहुत गुणी है, सुंदर है। माँ बोली-हमें एप्पल का मोबाइल चाहिए, आम नहीं। लड़का एक कोने में बैठा पब्जी खेल रहा था। बीच-बीच में कह देता-मम्मी, ले लो न, बहुत सुंदर है लड़की। और माँ बोली-हम सूरत नहीं, सूरत वाला फ्लैट देखेंगे।

विवाह-मंडप बना नहीं, पर तम्बू का ठेका हो गया। पंडित जी के पास पूजा से ज़्यादा दूल्हे की ईएमआई लिस्ट थी। जयमाला नहीं, एक्सचेंज ऑफ डिमांड लिस्ट हुआ। दूल्हे के भाई ने हँसते हुए कहा-ये सब तो नॉर्मल है, जैसे ही बारात निकलेगी, लड़की वाले 1 लाख नकद देंगे, बाक़ी स्टेज पर चेक से। लड़की की माँ फूट-फूटकर रोई, और सास ने कंधा थपथपाते हुए कहा-घबरा मत बहन, बेटी भेज रही है न, बकाया भी भेज देना। पंडित जी बोले-कन्यादान के साथ एक एसी, फ्रिज और 21 तोला सोना अनिवार्य है, अन्यथा मंत्र अधूरा रह जाएगा।

तिलक समारोह एक मिनी महंगाई-सम्मेलन बन चुका था। हर एक मेहमान बोली लगाने आया था। मैंने अपने बेटे की शादी में दो इनोवा ली थीं-एक रिश्तेदार ने गर्व से कहा। जैसे शादी नहीं, स्टील की फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा हो। लड़की के पिता ने जब अपनी सीमित आमदनी बताई तो लड़के की माँ ने कहा-हमने तो समझा था तुम NRI हो, ये तो निकले LIC एजेंट। लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि उसके मामा ने आँख मारी-बोल मत, वरना स्कूटी में बिदाई होगी। वो फिर PUBG में घुस गया-क्या यार, शादी हो रही है या सौदा? एक बार फूटकर बोला-मैं शादी नहीं करना चाहता पैसे पर! बाप ने थप्पड़ मारकर कहा-MBA में यही सिखाया गया था?

शादी की रात लड़की सज-धज के तैयार थी, पर दूल्हा नशे में टुन्न था। उसने पंडित जी से पूछा-आप पेटीएम लेते हैं? पंडित जी बोले-हम तो अब गूगल पे कराते हैं कन्यादान। लड़की की माँ रो-रोकर कह रही थी-हमने क्या बिगाड़ा था जो ये दिन देखना पड़ा? और दूल्हे के पापा मोबाइल पे होटल बुक कर रहे थे-शादी के बाद बेटे को मालदीव भेज देंगे, बीवी बाद में जाएगी जयमाल हो चुका था, लेकिन लड़की के पिता अभी तक वो पाँच हज़ार के नोटों वाली गड्डी खोज रहे थे जिसे उन्होंने रिश्तेदार के हाथ में दी थी। किसी ने कहा-नोटबंदी के बाद तो दहेज की कीमत और भी बढ़ गई है।

शादी खत्म हुई, विदाई आई। लड़की ने रोते हुए माँ से कहा-क्या मैं इंसान नहीं हूँ? माँ ने काँपते हाथों से सिर सहलाया-तू बेटी है, तेरी कीमत थी, पर तू बेशकीमती निकली। लड़की के पिता गाड़ी की छत पर वो झाड़ू, टेबल पंखा और जूठी थाली रखने लगे जो लड़की के साथ भेजनी थी-बिना इन सब के रिश्ता अधूरा माना जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हुई, लड़की ने पीछे मुड़कर देखा-बाप बैठा रो रहा था, माँ जमीन पर सिर पटक रही थी। और गाड़ी के शीशे पर लिखा था-"Thank you for your contribution in Groom Welfare Scheme."

दो साल बाद खबर आई-लड़की आत्महत्या कर चुकी है। वजह-हर महीने दहेज की नई किश्त। अंतिम चिट्ठी में लिखा था-पापा, अब मत रोना, बेटी थी, बिक गई। और गाँव के बच्चे एक चुटकुला सुना रहे थे-दूल्हा बिकाऊ है, पर रिश्तेदार गैर-रिफंडेबल हैं। समाज की हवाओं में एक सड़ांध थी जिसे अब हर साँस के साथ अंदर भरना था। गाँव के चौपाल पर एक बूढ़ा बोल पड़ा-अब लड़के नहीं होते, सिर्फ़ रेट लिस्ट होती है। अब भी आप पूछते हैं-दहेज बुरा है या नहीं? अब भी आप मुस्कराकर कहते हैं-चलो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो एक आख़िरी पंच सुनिए- जब बेटी की बिदाई नोटों से होती है, तो बेटियों की ज़िंदगी रसीद बन जाती है। और बेटों की डिग्री दहेज का इनवॉइस।

रजत पट से

मुकेश जोशी

समीक्षक

सितारों की भीड़ से अलग 'सितारे जमीन पर'

यह आमिर खान का ही बूता है कि बिना किसी स्टार सुपर स्टार के फिल्म बना लेना और उसे चला भी लेना। जैसे उनके प्रोडक्शन की एक सामान्य सी फिल्म 'लापता लेडीज' बिना किसी नामवर सितारे के सिर्फ कहानी पर ही चल निकली ऑस्कर तक गई। 'सितारे जमीन पर' भी दस ऐसे ही अपने आसपास के मानसिक कमजोर पात्रों को मजबूती से खड़ा करने की कहानी है। अपनी समस्याओं से घिरे और डरे आमिर खान को ऐसे ही बच्चों की बास्केटबाल टीम का कोच सजा के रूप में बना दिया जाता है जिन्हें उन असामान्य बच्चों को चैंपियंस की तरह न सिर्फ खेलना सिखाना वरन जिताना भी है।

किशोरावस्था और युवावस्था में कभी जुनून हुआ करता था कि फिल्म लगने के पहले दिन पहला शो देखना ही है हर हालत में हर हथकंडा हर जुगाड़ करके। टॉकीज के स्टाफ से लगाकर टिकट ब्लैक करने वालों से दोस्ती गांठी जाती थी। वो दौर पहले राजेश खन्ना फिर अमिताभ बच्चन का था जिनकी फिल्मों की टिकट हफ्तों महीनों आसानी से नहीं मिल पाती थी ऐसे में पहले दिन पहले शो की टिकट हथिया लेना वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत लेने जैसा गर्वोन्मति का भाव जगा देता था और यार दोस्तों के बीच अकड़ भी। फिल्मों का वो भीड़ भरा दौर धीरे धीरे खत्म होता गया न राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जैसे लार्जर देन लाइफ अभिनेता बाद में आए। फिल्में तो बनती रहीं चलती भी रहीं समय के हिसाब से। उस दौर में 25 50 हफ्ते फिल्म बिना प्रमोशन बिना प्रचार के चल जाती थी आज तो 25 दिन में ही हांफने लग जाती है। तब सिंगल स्क्रीन थियेटर जिन्हें हम ठाटिया टॉकीज बोलते थे और वे होते भी ऐसे ही थे भी।

अमिताभ राजेश के बाद सनी देओल अजय देवगन और कुछ हद तक अनिल कपूर ही थोड़े सशक्त हीरो बनकर आए जिनके दम पर फिल्में चला करती थीं। खान गैंग के बौने खानों की कुछ फिल्में अपनी अपनी वजहों और जबरदस्त मार्केटिंग से भले चल गई हों लेकिन पहले दिन पहले शो का आकर्षण कभी पैदा नहीं कर सकीं। अलबत्ता खान गैंग के इकलौते प्रतिभाशाली अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्मों के अलग चयन, नई कहानियों की वजह से दर्शकों को अपनी ओर खींचते रहे।कोई 40 साल बाद फिर से किसी फिल्म का पहले दिन पहला शो देखने में आया तो वो आमिर खान की ही फिल्म 'सितारे जमीन पर' है। इस बहुचर्चित फिल्म के प्रोमोज देखकर ही लगा था कि ये फिल्म पहले ही दिन देखने लायक है इससे पहले कि कोई विपरीत प्रतिक्रिया सुनने को मिल जाए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। फिल्म के बारे में इतना तो पता चल ही गया था कि यह समाज के विशिष्ट बच्चों को लेकर बनाई गई है जिनका अभिनय और फिल्मी दुनिया से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। आमिर खान के अद्भुत साहस की तारीफ करना होगी कि अपने आसपास के ऐसे कई बच्चों जिन्हें हम पागल करार देते हुए उनसे बात भी न करते हुए उल्टे उन्हें दुरदुराते रहते हैं चूंकि वे बच्चे अपने प्रति समाज के उपेक्षा भाव को समझ नहीं पाते इसलिए वे रिएक्ट भी नहीं करते। पर संवेदनशील अभिनेता आमिर खान ने इन मासूमों को आवाज देकर इनको सितारा बना दिया है।

यह आमिर खान का ही बूता है कि बिना किसी स्टार सुपर स्टार के फिल्म बना लेना और उसे चला भी लेना। जैसे उनके प्रोडक्शन की एक सामान्य सी फिल्म 'लापता लेडीज' बिना किसी नामवर सितारे के सिर्फ कहानी पर ही चल निकली ऑस्कर तक गई। 'सितारे जमीन पर' भी दस ऐसे ही अपने आसपास के मानसिक कमजोर पात्रों को मजबूती से खड़ा करने की कहानी है। अपनी समस्याओं से घिरे और डरे आमिर खान को ऐसे ही बच्चों की बास्केटबाल टीम का कोच सजा के रूप में बना दिया जाता है जिन्हें उन असामान्य बच्चों को चैंपियंस की तरह न सिर्फ खेलना सिखाना वरन जिताना भी है। अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियों से जूझते हुए भी इन विशिष्ट बच्चों को अपने दम पर खड़ा करना और कोलकाता के फाइनल तक ले जाने की कथा को बेहद मनोरंजक तरीके से बुना है। 'सितारे जमीन पर' में दर्शक जरा भी बोझिल नहीं होते पहले दृश्य से ही फिल्म गति पकड़ लेती है। फिल्म के सितारे मंदबुद्धि होते हुए भी सब रोजगाररत हैं घर में बैठे हुए अपने अभिभावकों पर आश्रित नहीं। चाहे वो किसी होटल के किचन में बर्तन मांजने धोने का काम ही क्यों न हो। फिल्म थोड़ी बहुत कहीं ढीली हुई है तो आमिर जेनेलिया की जबरन पैच की गई प्रेम विछोह की कहानी की वजह से।

इसकी बजाय तो थोड़ी देर के लिए ही सही आमिर की मां डॉली अहलूवालिया के प्रसंग और बृजेन्द्र काला के साथ उनकी लव स्टोरी ज्यादा रोचक है। नए सितारे अपने सहज स्वाभाविक अभिनय और चुटिले संवादों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। वहीं खान गैंग में से इकलौते उत्कृष्ट अभिनेता आमिर खान इस फिल्म में थोड़े चुके से लगते हैं वे दोहराव के शिकार हो रहे हैं। 'दंगल' के बाद से आमिर के अभिनय की स्वाभाविकता कम होती दिख रही है। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर तनाव और शिकन दिखाई दी है जो शायद कहानी की जरूरत नहीं थी। आमिर को अपने अभिनय पक्ष पर रिव्यू करना चाहिए। आमिर से अच्छा सहज अभिनय तो करतार बने गुरुपालसिंह कर गए हैं। फिल्म का सबसे सकारात्मक और अच्छा पक्ष सुनील यानी आशीष पेंडसे हैं जो हमारे मप्र के खंडवा से चुनकर ले जाए गए हैं।

आशीष फिल्म के पहले दृश्य से लगाकर बीच बीच में कई बार अपनी सशक्त उपस्थिति अंतिम दृश्य तक दर्ज करवाते हैं। आशीष की प्रतिभा से सचिन तेंदुलकर और शंकर महादेवन तक प्रभावित हुए हैं। आमिर खान के इस जोखिम भरे सार्थक प्रयास की हर संवेदनशील दर्शक सराहना ही करेगा। फिल्म का गीत संगीत पक्ष भी दोहराव भरा है। अलबत्ता राम संपत का पार्श्व संगीत फिल्म की गति में सहायक ही है।जेनेलिया के लिए ज्यादा कुछ करने को था नहीं ऊपर से उनकी भावहीन संवाद अदायगी। इस सबके बावजूद बरसों बाद देखे पहले दिन पहले शो के 'सितारे जमीन पर' के श्रेष्ठ सितारों और इन्हें सितारा बनाने वाले आमिर खान को उनके अभिनव अनूठे प्रयास के लिए नमन तो किया ही जा सकता है। सेल्यूट आमिर आपकी प्रतिबद्धता के लिए।

शिक्षा व्यवस्था

श्याम कुमार कोलारे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

चिंता का कारण है हर साल घट रही सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या

सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या के पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है निजी स्कूलों का बढ़ता वर्चस्व। असर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मध्यप्रदेश में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में नामांकन लगातार बढ़ता रहा है, जो 2024 तक 30.5 फीसदी तक पहुंच गया है। कुछ कारणों में ये भी देखा गया कि सरकारी और निजी स्कूलों के तुलनात्मक आंकड़े यह दिखाते हैं कि निजी विद्यालयों में बच्चों का सीखने का स्तर तुलनात्मक रूप से बेहतर है। उदाहरण के लिए, 2024 में सरकारी स्कूलों में 37.5 फीसदी बच्चे कक्षा -2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, जबकि निजी स्कूलों में यह प्रतिशत 58.1 फीसदी है। गणित के क्षेत्र में भी निजी स्कूलों में सुधार अधिक 5.8 फीसदी रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में केवल 1.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि, यह सुधार सकारात्मक है, परंतु 2024 में भी पढ़ाई 48.8 फीसदी और गणित 30.7 फीसदी में राज्य का स्तर अखिल भारतीय औसत से कम बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी सरकारी स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता और आधारभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है। यह केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समान अवसर और एक बेहतर भविष्य की आधारशिला है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां सामाजिक और आर्थिक विषमता गहरी जड़ें जमा चुकी है, वहाँ सरकारी स्कूल हमेशा से उन बच्चों की आशा रहे हैं जो निजी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। लेकिन हाल के वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से मध्यप्रदेश जैसे राज्य में यह गिरावट चिंताजनक रूप ले चुकी है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में तो कई स्कूलों को बच्चों की कम उपस्थिति के कारण बंद भी कर दिया गया है। यह स्थिति केवल एक शैक्षणिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और नीति-निर्माण के स्तर पर गंभीर संकट का संकेत है।

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आँकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन की संख्या हर साल घटती जा रही है। खासकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां कुल छात्रों की संख्या 10 से भी कम रह गई है। इस कारण से राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों स्कूलों को या तो बंद कर दिया है या पास के स्कूलों में मिला दिया है। यह कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका व्यापक सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्कूलों का बंद होना केवल एक भवन का बंद होना नहीं है, बल्कि यह उस क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा से दूरी की शुरुआत भी है। छोटे नामांकन के कारण मल्टी-ग्रेड कक्षाएं बनती हैं, जहाँ एक शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। इससे सीखने का स्तर प्रभावित होता है, जैसा एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 अनुसार मध्यप्रदेश (ग्रामीण) में कक्षा पाँचवीं के आधे से अधिक बच्चे कक्षा दो स्तर का पाठ पढ़ सकने में असक्षम है। जबकि बच्चों को पूरे पांच साल स्कूल में गुजरने के बाद कम से कम उसे अपनी भाषा के पठन का पूरा ज्ञान होना चाहिए था। गणित की स्थिति भी लगभग यही बनी हुई है, रिपोर्ट अनुसार कक्षा 5 के चार में से एक बच्चे ही सामान्य भाग का सवाल कर पाते है, जो कि एक चिंता का विषय है।

सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या के पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है निजी स्कूलों का बढ़ता वर्चस्व। असर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मध्यप्रदेश में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में नामांकन लगातार बढ़ता रहा है, जो 2024 तक 30.5 फीसदी तक पहुंच गया है। कुछ कारणों में ये भी देखा गया कि सरकारी और निजी स्कूलों के तुलनात्मक आंकड़े यह दिखाते हैं कि निजी विद्यालयों में बच्चों का सीखने का स्तर तुलनात्मक रूप से बेहतर है। उदाहरण के लिए, 2024 में सरकारी स्कूलों में 37.5 फीसदी बच्चे कक्षा -2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, जबकि निजी स्कूलों में यह प्रतिशत 58.1 फीसदी है। गणित के क्षेत्र में भी निजी स्कूलों में सुधार अधिक 5.8 फीसदी रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में केवल 1.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि, यह सुधार सकारात्मक है, परंतु 2024 में भी पढ़ाई 48.8 फीसदी और गणित 30.7त्रफीसदी में राज्य का स्तर अखिल भारतीय औसत से कम बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी सरकारी स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता और आधारभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज गांवों और कस्बों तक में निजी विद्यालय खुल गए हैं जो स्मार्ट क्लास, अंग्रेजी माध्यम और 'बेहतर अनुशासन' जैसे आकर्षक वादे करते हैं। अभिभावक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की तलाश में निजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों की छवि एक प्रकार से 'गरीबों के स्कूल' की बन गई है, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग उनसे दूरी बनाने लगा है। यह छवि बदलाव की माँग करती है, परंतु इसके लिए केवल प्रचार या नारेबाज़ी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर सुधार लाना अनिवार्य होगा। शिक्षा की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों से मोहभंग होता जा रहा है। शिक्षकों की नियमित अनुपस्थिति, अधूरी भर्ती और प्रयोगात्मक शिक्षण के अभाव ने बच्चों की सीखने की रुचि को प्रभावित किया है। कई स्कूलों में विज्ञान या गणित जैसे विषयों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर से भारी प्रशासनिक कार्यों में शिक्षकों की व्यस्तता उन्हें बच्चों की पढ़ाई से दूर कर देती है। जब बच्चों को समय पर पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता, शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं होता और कक्षा में नवाचार नहीं होता, तो वे स्कूल आने से कतराने लगते हैं और धीरे-धीरे विद्यालय खाली होने लगते हैं। इन सबके साथ एक सामाजिक पहलू भी जुड़ा है जो कम ध्यान में आता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई सरकारी स्कूल बंद होता है, तो बच्चों को आसपास के अन्य स्कूलों में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह दूरी विशेष रूप से छोटी कक्षाओं के बच्चों, बालिकाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाती है। माता-पिता अपनी बेटियों को दूर भेजने से हिचकते हैं, जिसके कारण कई बार उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। इससे लड़कियों के शिक्षा स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ता है और बाल-विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं फिर से सिर उठाने लगती हैं।

इसके अलावा, सरकारी स्कूल स्थानीय समुदाय के लिए केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होते, बल्कि रोजगार, सामाजिक मेलजोल और सामूहिक विकास का आधार भी होते हैं। जब कोई स्कूल बंद होता है तो वहाँ काम करने वाले शिक्षक, रसोइया, सफाईकर्मी और अन्य सहायक कर्मियों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। यह केवल एक संस्थान का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक पूरे समुदाय का संकुचन होता है। इस समस्या का समाधान केवल स्कूल बंद करने या उन्हें मर्ज करने में नहीं है, बल्कि इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने में है। सबसे पहले शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बदलते समय के साथ नई शिक्षण विधियों को अपना सकें। बाल-केंद्रित और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की रुचि बनाए रखना ज़रूरी है। स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल के साधन जैसे संसाधनों की उपलब्धता विद्यालयों को बच्चों के लिए आकर्षक बना सकती है। इसके साथ ही, अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना भी आवश्यक है। यदि स्कूल को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ स्थानीय लोग समय-समय पर बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और प्रगति की समीक्षा कर सकें, तो अभिभावकों का विश्वास बहाल किया जा सकता है। पंचायतों और स्थानीय निकायों को विद्यालय प्रबंधन समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह केवल नामांकन बढ़ाने पर ध्यान न दे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल में ठहरें और सीखें। स्कूलों को नकारात्मक छवि से निकाल कर सकारात्मक पहचान देने की आवश्यकता है। 'सरकारी स्कूल' शब्द को 'जन शिक्षा केंद्र' जैसे सशक्त नामों से बदलकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। जब कोई सरकारी स्कूल नवाचार, सफलता और गुणवत्ता का प्रतीक बनेगा, तब ही समाज का भरोसा लौटेगा।

नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे स्कूलों को बंद करने के निर्णय से पहले उसके सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। स्कूलों को क्लस्टर मॉडल में विकसित किया जा सकता है, जिसमें पास-पड़ोस के स्कूल मिलकर संसाधन साझा करें और शिक्षक संयुक्त रूप से कार्य करें। डिजिटल लर्निंग, रेडियो क्लास, मोबाइल लाइब्रेरी जैसी पहलों को भी सरकारी स्कूलों में समाहित किया जा सकता है। अंततः, यह स्वीकार करना होगा कि सरकारी स्कूल केवल शिक्षा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समानता और अवसर के वाहक हैं। यदि यह तंत्र टूटता है, तो समाज के कमजोर वर्गों की उम्मीदें टूटती हैं। हमें यह तय करना होगा कि क्या हम शिक्षा को केवल बाजार की वस्तु बनने देना चाहते हैं, या फिर इसे एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में सुदृढ़ बनाए रखना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जरूरत अब केवल एक शैक्षणिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। अगर हम चाहते हैं कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, एक समान शिक्षा पाए, तो हमें सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय उनमें जान डालनी होगी। यही रास्ता हमें एक शिक्षित, समावेशी और प्रगतिशील भारत की ओर ले जाएगा।

पुण्यतिथि

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

राष्ट्रमाता रानी दुर्गावती- वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक

भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम उस अमर पंक्ति में अंकित है, जहाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली वीरांगनाओं की गाथाएँ स्वर्णाक्षरों में लिखी गई हैं। 24 जून, 1564 को जब गोंडवाना की रानी ने मुगलों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की, तो वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि 'भारत माता की सच्ची पुत्री' बन गईं। उनकी पुण्यतिथि आज भी स्वाभिमान, आत्मबल, और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष की प्रेरणा देती है।

स्वतंत्र गोंड राज्य की महारानी

रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर (वर्तमान बाँदा, उत्तर प्रदेश) के चंदेल राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा कीर्तिसिंह चंदेल एक वीर और स्वाभिमानी शासक थे। दुर्गावती को बचपन से ही अस्त्र-शस्त्र, घुड़सवारी, राजनीति, शिकार और युद्धनीति की गहन शिक्षा दी गई। उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ जो गढ़मंडला (वर्तमान जबलपुर) के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। इस विवाह ने न केवल दो शक्तिशाली राजवंशों- चंदेल और गोंड- को जोड़ा, बल्कि सामाजिक समरसता और आदिवासी-सामंती एकता का भी प्रतीक बना।

प्रशासनिक दृष्टि

राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने विधवा होते हुए भी न केवल राज्य की बागडोर संभाली बल्कि अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया। उन्होंने 'नारी नेतृत्व की एक सशक्त परंपरा' की नींव रखी, जहाँ मातृत्व और राज्य-कुशलता दोनों का समन्वय दिखाई देता है।

रानी ने अपने शासनकाल में कृषि, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली को संगठित किया। वह प्रतिदिन प्रजावात्सल भाव से जनता से संवाद करतीं, और निर्णयों में लोकहित सर्वोपरि रहता। उन्होंने 'रेवा (नर्मदा) तट' पर अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया, जिनमें रानी ताल प्रमुख है।

संघर्ष : जब मुगलों ने गोंडवाना को ललकारा

रानी दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना राज्य एक स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्र था। इसी कारण मुगल बादशाह अकबर के सूबेदार आसफ खाँ की लालची दृष्टि इस राज्य पर पड़ी। उसने 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने पराजय के भय के बजाय स्वाभिमान से युद्ध का विकल्प चुना। उन्होंने केवल 20 हजार सैनिकों के साथ आसफ खाँ की विशाल सेना का सामना किया। युद्ध 'नर्रई के जंगलों' में हुआ, जहाँ रानी स्वयं हाथी 'सरस्वती' पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरीं। इस युद्ध में रानी के वीर पुत्र वीर नारायण शहीद हो गए। स्वयं रानी को भी कई घाव लगे, पर वे पीछे नहीं हटीं। जब पराजय सुनिश्चित हो गई और बंदी बनने की आशंका बढ़ी, तो रानी ने मुगलों के हाथ न आने का प्रण निभाते हुए आत्मबलिदान कर दिया। 24 जून 1564 का यह दिन, भारतीय इतिहास में 'नारी अस्मिता और वीरता की पराकाष्ठा' बन गया।

भारतीय संस्कृति की प्रतीक

रानी दुर्गावती केवल एक योद्धा नहीं थीं, वे धार्मिक सहिष्णुता, प्रजाहित, नारी नेतृत्व, राजधर्म और स्वतंत्रता के गौरव की प्रतीक थीं। उन्होंने आदिवासी संस्कृति को आत्मसात कर गोंड समाज को गौरव दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि 'राजनीति में मातृत्व, नारीत्व और राष्ट्रप्रेम' कैसे एक साथ निभाए जा सकते हैं। रानी दुर्गावती भारतीय स्त्री शक्ति की प्रतीक हैं, जिन्होंने नारी को केवल श्रृंगार या समर्पण का नहीं, बल्कि शौर्य और स्वराज्य का प्रतीक बनाया। आज जब भारत 'नारी सशक्तिकरण' और 'जनजातीय उन्नयन' की बात कर रहा है, रानी दुर्गावती का बलिदान एक 'आदर्श प्रतीक' बनकर उभरता है:

जनजातीय समाज के लिए वह 'पहली राष्ट्रीय नायिका' हैं

मप्र सरकार ने उनके सम्मान में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा, और 1983 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया।

रानी दुर्गावती का जीवन इस सत्य को पुष्ट करता है कि 'राज्य का गौरव केवल पुरुषों की तलवारों से नहीं, बल्कि स्त्रियों के त्याग और शौर्य से भी सुरक्षित रहता है।' उनकी पुण्यतिथि केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं, बल्कि यह आत्ममंथन और आत्मबोध का दिन है - कि क्या हम उस नारी परंपरा और जनजातीय अस्मिता को सम्मान दे पा रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए रानी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? स्मरण श्लोक: वीरांगना वह दीप है, जो अंधकार में जला करती है। दुर्गावती नाम है उसका, जो रणभूमि में अमर हुआ करती है।

कार पलटी, वकील की मौत, 5 घायल

बैतूल। सारणी के नावघाट के पास रविवार रात वकीलों से भरी एक कार राजडोह टर्निंग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में सलैया निवासी वकील सुरेश सुमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार बसंत साकरे (सारनी), रामपत गुव्हाडे (शोभापुर), सतीश मालवीय, सूरज तिवारी (बगडोना) और राकेश महाले (सारनी) घायल हो गए। घायलों को घोड़ाडोंगरी और सारनी के अस्पतालों में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के समय कार तेज रफ्तार में थी। कार में सवार वकील राकेश महाले ने बताया कि वे सभी नावघाट घूमने गए थे। लौटते समय नावघाट के पास स्थित राजडोह की टर्निंग पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोबरा का किया रेस्क्यू

बैतूल। शहर के रामनगर इलाके में रविवार रात बाइक के हैंडल मास्क में कोबरा छिपा मिला। बाइक मालिक गोपाल बर्डे को अचानक कुछ आवाज सुनाई दी तो उन्होंने पास जाकर देखा। हैंडल के भीतर से कोबरे की सरसराहट हो रही थी। परिवार घबरा गया और तुरंत सर्पमित्र को बुलाया गया। सूचना मिलते ही सर्पमित्र विशाल मौके पर पहुंचे और देखा कि बाइक के मास्क में कोबरा फंसा हुआ था और फुंफकार रहा था। रात के अंधेरे और संकरी जगह होने के बावजूद विशाल ने बिना समय गंवाए सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान मोहल्ले के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए।कोबरा को पकडने के बाद विशाल ने उसे सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ दिया। विशाल विश्वकर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर गर्म और सूखी जगह की तलाश में घरों, वाहनों और अन्य संकरे स्थानों में घुस जाते हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। यदि किसी को सांप दिखाई दे तो खुद छेड़छाड़ न करें, तुरंत प्रशिक्षित सर्पमित्र या वन विभाग को सूचना दें।

दनोरा गांव का फोरलेन से टूटा संपर्क, महिलाएं पहुंचीं कलेक्ट्रेट

बैतूल। दनोरा गांव का संपर्क फोरलेन निर्माण के बाद से पूरी तरह बाधित हो गया है। पहले यह गांव एनएच-47 की टू लेन सडक़ से जुड़ा था, लेकिन बंसल कंपनी के फोरलेन बनाने के बाद रास्ता बंद कर दिया गया। इस समस्या से परेशान होकर सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं और संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अब गांव में कोई यात्री बस नहीं आती। बैतूल और चिचोली से आने वाली बसें या तो गांव के बाहर रुकती हैं या फोरलेन से निकल जाती हैं। स्थिति यह है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को रात में 1 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि रात के समय असुरक्षा का भय रहता है। मडक़ मार्ग चंडी मंदिर के पास रास्ता खोलने की मांग भी ठुकरा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के अन्य गांवों को तो फोरलेन से जोड़ दिया गया, लेकिन दनोरा को नजरअंदाज कर दिया गया। चिचोली से आने वाली बसें अब जीन के पास ही रुकती हैं। बस कंडक्टर साफ कह देते हैं कि दनोरा नहीं जाएंगे। गांव के प्रतिनिधि मुकेश गलकर ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही दनोरा को फोरलेन से नहीं जोड़ा गया तो ग्रामीण फोरलेन पर चक्का जाम करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामले में संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद ने बताया कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों और परिवहन विभाग के जिला प्रमुख से इस संदर्भ में चर्चा की है। यहां हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को कहा गया है कि वे गांव तक पहुंचने के लिए हाईवे से पहुंच मार्ग बनाएं। बस संचालकों ने भी अपने लिए यही समस्या बताई है। जल्द समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा।

विनोबा नगर में मनाई डॉ. मुखर्जी की पुण्यतिथि

बैतूल। विनोबा नगर में सोमवार 23 जून को जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में वार्डवासियों ने भाग लिया और डॉ. मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में विशेष रूप से पार्षद

शिला पिंटू महाले उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे विचारक और राष्ट्रनायक थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जम्मू-कश्मीर में एक देश, एक विधान, एक निशान के लिए उनका आंदोलन आज भी प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे डॉ. मुखर्जी के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर हों। इस अवसर पर नगर के प्रमुख समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि जितेंद्र जैन, रवि हीरानी, खेमचंद टेनू साहू, शिवराज परिहार, राजकुमार वर्मा, नरेंद्रचंद्र राठौर, सरिता खाड़े, सुमन कुशवाहा, पूजा पवार एवं समोती साहू भी उपस्थित रहे। सभी ने डॉ. मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बारिश से कटाव बढ़ने से प्रभावित हो सकता है मार्ग

पुल-पुलिया के समीप हुए कटाव को अब तक नहीं भरा

बैतूल। बारिश से एक साल पहले जिन पुल-पुलिया का कटाव यानि पुल-पुलिया के किनारे से मिट्टी बही थी, उन्हें अभी तक नहीं भरा गया है। इससे भविष्य में पुलिया या सडक़ धंसने की संभावनाएं बढ़ गई है। शहर के कुछ स्थानों पर हालात यह है कि संकरे पुल-पुलिया के दोनों ओर कटाव है। इस कारण बारिश में दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। शहर के करबला घाट के दोनों ओर संकरे कटाव के कारण वाहनों के गिरने और अनियंत्रित होकर स्लिप होने की घटनाएं होती हैं। यहीं हाल शहर के गंज क्षेत्र में मोक्षधाम के समीप के संकरे पुल के समीप भी है, यहां कटाव के कारण पहले भी बाइक सवारों को चोटें आ चुकी है और वाहनों की टूट-फूट की घटनाएं हुई हैं। बता दे कि शहर के कालापाठा, हमलापुर, गाड़ाघाट और करबला पुलिया के बगल में मिट्टी गायब हो गई है। करबला में तो पुलिया के ऊपर डामर ही रह गया है, नीचे से मिट्टी धंसक गई है। 6-6 फीट गहरे कटाव हो गए हैं। लेकिन नगरपालिका या पीडब्ल्यूडी ने किसी भी जगह पर मरम्मत नहीं करवाई है। इस कारण अधिकांश जगह अब बारिश में खतरा मंडरा रहा है। यहां पर बारिश में वाहनों के गिरने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

कई जगहों पर सड़क तक पहुंचा कटाव

व्यस्ततम सडक़ों की पुल-पुलिया पर मिट्टी के कटाव के कारण आवागमन जोखिम भरा गया है। जिसका कारण यह है कि पुल-पुलिया के समीप मिट्टी का कटाव सडक़ तक पहुंच गया है। ऐसे में समय रहते कटाव नहीं भरा तो बारिश में यह कटाव और बढ़ जायेगा। इस स्थिति में कोई भारी वाहन पुल-पुलिया से गुजरता है तो जमीन धंसने या सडक़ धंसने से बड़ा हादसा भी हो सकता है। करबला पुल के पास रोड के ऊपर डामर है, नीचे मिट्टी पूरी धंसक गई है। बारिश तेज हुई तो यहां पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर सामान्य कारों के साथ बस और ट्रक भी गुजरते हैं। यहां पर रेत की बोरियों की दीवार तक नहीं बनाई है। जिससे वाहन चालकों में इस पुल को पार करते समय हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है।

कुछ पुल-पुलिया निर्माण की मिली मंजूरी

शहर की अंदरूनी और बाहरी सडक़ों पर बने पुल-पुलियाओं के किनारे मिट्टी के कटाव के कारण बड़े-बड़े गड्ढे निर्मित हो गये है। खासकर गाड़ाघाट के समीप स्थित नाले पर पुल में कटाव होने से बारिश में बाढ़ का खतरा बना रहता है। गाड़ाघाट रोड पर पुल का निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं गंज से करबला तक सडक़ निर्माण भी स्वीकृत हो गया है। इन सडक़ों पर पुल निर्माण होने से बारिश में आवागमन बाधित नहीं होगी। इससे शहर की कारगिल चौक, अखाड़ा चौक, गाड़ाघाट होते हुए पुराने एनएच तक का आवागमन आसान होगा। लेकिन जिन पुल-पुलिया के निर्माण को स्वीकृति नहीं मिली है, ऐसे पुलिया से गुजरते समय वाहनों में हादसे का डर बना रहता है।

आधा दर्जन स्थानों पर यहीं स्थिति

शहर के आधा दर्जन से अधिक पुल-पुलियाओं पर मिट्टी के कटाव से बडे-बड़े गड्ढे बन गये है। कुछ पुलिया का कटाव सडक़ तक पहुंच गया है। जिसमें गाड़ाघाट पुलिया पर भी कटाव है, हालांकि इस पुल के निर्माण स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इसके अलावा करबला घाट के पहले नाले के ऊपर की पुलिया, आरामशीन क्षेत्र में स्थित पुलिया के पास कटाव हो रहा है, यहां से मिट्टी गायब हो गई है, जबकि इस सडक़ पर कालापाठा का पूरा ट्रैफिक गुजरता है। गंज में मैकेनिक चौक के समीप नाले की पुलिया के ऊपर से कटाव है, यहां से रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन जाते हैं। माचना नदी के किनारे हमलापुर-मलकापुर मार्ग की पुलिया के बगल में भी कटाव हो रहा है। यहां से हमलापुर और मलकापुर के बीच वाहनों की आवाजाही होती है।

इनका कहना है -

पुल-पुलिया के किनारे मिट्टी का कटाव कहां-कहां हुआ है, इसकी जानकारी व्हाटसएप पर भेज दीजिए। मैं इस संबंध में नपा इंजीनियरों से चर्चा करता हूं, जो भी सुधार के लिए आवश्यक है, प्रयास किया जायेगा।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

अंतरराष्ट्रीय नशा दिवस पर युवाओं ने ली नशामुक्त भारत की शपथ

रंगोली और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से दिया नशामुक्ति का संदेश

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल में अंतरराष्ट्रीय नशा दिवस के उपलक्ष्य में नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाइयों द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में जिला संगठक डॉ. सुखदेव डोंगरे, कार्यक्रम अधिकारी प्रो. शंकर सातनकर, प्रो. गीता माली, प्रो. योगेश्वरी पवार, प्रो. संतोष पवार एवं डॉ. गोपाल प्रसाद साहू की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विद्यार्थियों के बीच नशामुक्ति विषय पर निबंध लेखन एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में खुशी पारखे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान कशिश धाड़से को और तृतीय स्थान खुशी सिरसाम को मिला। वहीं, निबंध प्रतियोगिता में कशिश धाड़से ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान कीर्ती अडलक और तृतीय स्थान अनुज धुर्वे को मिला। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली और नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिमांशु पाटिल, अक्षय मालवी, आयुष घिंडोडे, दीपाली गायकवाड़, आयुष नागोरे, कल्पना धुर्वे, कमानी खवसे, दिशा राठौर, सोनू कुशवाहा, विक्रम पहाड़े, करण धाड़से, दुर्गेश धुर्वे सहित अन्य 10 स्वयंसेवकों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में विलंब बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर

कलेक्टर की अध्यक्षता में समयसीमा की बैठक आयोजित

बैतूल। बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में जनसामान्य को समय पर सीधा लाभ मिले। इसके लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करें। यह निर्देश कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में आयोजित समय सीमा की बैठक में दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश सभी विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि 50 दिवस से अधिक की शिकायतों के निराकरण पर भी सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। कोई भी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरते। उन्होंने एग्रीकल्चर, स्कूल शिक्षा विभाग, लेबर, सामाजिक न्याय विभाग, टेक्निकल एजुकेशन, ट्राइबल वूमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक शिकायतों वाले विभाग प्राथमिकता से अपनी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं।

अंत्येष्टि, अनुग्रह सहायता के प्रकरणों के निराकरण में लाए प्रगति.....

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने पीएचई विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में हर घर नल से जल में प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा कर सभी नपा सीएमओ को योजना के तहत बनाए गए आवास पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीओ तथा संबंधित अधिकारियों को नामांकन, सीमांकन, डायवर्सन, बटवारा के प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर श्री सूर्यवंशी टेक्निकल एजुकेशन, वूमेन चाइल्ड, पब्लिक हेल्थ, लेबर डिपार्टमेंट सहित अन्य विभागों को रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नजूल पट्टों, धारा 20 केसेस, भूमि आवंटन केस, वसूली के कार्यों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ई-ऑफिस व्यवस्था के तहत फाइल्स का करें संचालन...

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कोई भी विभाग अब हार्ड कॉपी में फाइल का संचालन नहीं करेगा। सभी विभाग ई ऑफिस व्यवस्था के तहत फाइल्स का संचालन करें। सभी अपने कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन अभियान की गतिविधियां सतत जारी रहे। अभियान के कामों की विस्तृत जानकारी निर्धारित पोर्टल पर भी अपलोड करें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन को टीकाकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी सीएमओ और जनपद सीईओ को समग्र ई-केवाईसी में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ठेकेदार और नगरपालिका की अनदेखी ने वार्डवासियों को किया परेशान

बैतूल। बारिश शुरू होने से पहले ही लोहिया वार्ड की सडक़ की दुर्दशा को लेकर नगरपालिका को आगाह किया गया था, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई। अब पहली ही बारिश में वह अंदेशा हकीकत में बदल गया है और वार्डवासी इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। संकरी गली में पाइपलाइन बिछाने के बाद सडक़ को मिट्टी से पाटकर छोड़ दिया गया था, जिसे दोबारा पक्का करने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं निभाई। नतीजा यह है कि अब यह सडक़ दलदल में तब्दील हो गई है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों, दुकानदारों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत वितरण कंपनी भग्गूढाना के पास स्थित संकरी

गली में जब पाइप लाइन डाली गई, तब सडक़ को बीच से खोदकर मिट्टी से पाट दिया गया था। लेकिन दोबारा कंक्रीट या डामर से पक्का करना नगर पालिका और ठेकेदार दोनों ने जरूरी नहीं समझा। परिणामस्वरूप यह गली अब दलदल में बदल चुकी है, स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, दोपहिया वाहन सवार और दुकानदार सभी कीचड़ से परेशान हैं। लोहिया वार्ड में स्थित दो किराना दुकानों पर कीचड़ की वजह से ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुकानदारो ने बताया कि लगभग दो महीने से सडक़ की मरम्मत नहीं की गई है और अब बारिश शुरू होने से हालात और भी बदतर हो गए हैं। ग्राहकों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे दुकानदारी पर संकट आ गया है। इन दुकानदारों का कहना है कि यदि जल्द सडक़ निर्माण नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में दुकान बंद करनी पड़ेगी। इसी गली से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन और कीचड़ के कारण कई बच्चे गिर चुके हैं। बच्चों के माता-पिता रोज डर के साए में बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं।।वार्डवासियों ने कई बार नगर पालिका को शिकायतें कीं लेकिन हर बार यही कहा गया कि यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संबंधित ठेकेदार की लापरवाही से पूरा वार्ड मुश्किल में है और अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह समस्या और विकराल हो सकती है।

घाट सेक्शन में अतिरिक्त इंजन नहीं मिला

धाराखोह स्टेशन पर रुकी रही दक्षिण एक्सप्रेस

बैतूल। हैदराबाद जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस को बैतूल के धाराखोह रेलवे स्टेशन पर 50 मिनट तक रोकना पड़ा। वजह- घाट क्षेत्र में ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इंजन (बैंकर) नहीं मिल पाया। जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 12722 इटारसी से घोड़ाडोंगरी होते हुए धाराखोह तक समय पर पहुंची। लेकिन अगले स्टेशन मरामझिरी तक जाने के लिए बैंकर की कमी के कारण रुकना पड़ा। बैतूल स्टेशन मैनेजर वीके वाकडे ने इस देरी की पुष्टि की। दरअसल, धाराखोह से मरामझिरी स्टेशन के बीच मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को बैंकर की जरूरत होती है। धाराखोह घाट सेक्शन में सामान्य इंजन पूरी रफ्तार से ट्रेन नहीं खींच पाते। इसलिए पीछे से धकेलने के लिए अतिरिक्त इंजन लगाया जाता है। रेलवे ने मरामझिरी-धाराखोह स्टेशन पर 4 बैंकर तैनात किए हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट की कमी का मामला है। बेहतर समय प्रबंधन से सभी मेल एक्सप्रेस को बैंकर मिल सकता था। धाराखोह स्टेशन समुद्र तल से 445 मीटर और मरामझिरी स्टेशन 644 मीटर की ऊंचाई पर है। इस 200 मीटर के अंतर को पार करने के लिए बैंकर जरूरी है। कभी-कभी अप ट्रैक पर भी बैंकर का उपयोग किया जाता है, ताकि ट्रेन ढलान पर तेजी से न उतरे।

रानी दुर्गावती बलिदान दिवस आज

बैतूल। समस्त आदिवासी समाज संगठन के तत्वावधान में आज मंगलवार 24 जून को रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम लाल बहादुर स्टेडियम के सामने सुबह 9 बजे से गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बलिदान दिवस कार्यक्रम के माध्यम से रानी दुर्गावती के अद्वितीय शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के लिए दिए गए बलिदान को स्मरण किया जाएगा।

विधायक के प्रयासों से मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माण को मिली रफ्तार

विशाल पार्किंग, लिफ्ट और 300 दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा बैतूल की शान

बैतूल। बैतूल के हृदयस्थल गंज क्षेत्र में वर्षों से अधर में लटके बहुप्रतीक्षित गंज मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर अब सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के विशेष प्रयासों से नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को नया स्वरूप मिला है। अब इस भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नई निविदा जारी कर दी गई है। अब 27 जून को इस महत्वाकांक्षी योजना के ई-टेंडर खुलेंगे। वर्ष 2015 में विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा इस योजना की नींव रखी गई थी। उन्होंने गंज क्षेत्र में मौजूद सभी छोटे-बड़े व्यापारियों से बैठक कर उनकी आवश्यकताओं को समझा और एक सुव्यवस्थित, सुविधायुक्त और आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण की योजना को मूर्त रूप देने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया था। योजना का पहला टेंडर 2017 के अंत में जारी हुआ और निर्माण कार्य की शुरुआत भी की गई, लेकिन निर्माण कार्य बार-बार अटकता रहा। विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों के चलते कार्य स्थगित होता रहा। पुरानी एसओआर दरें, बाजार में निर्माण सामग्री की महंगाई और ठेकेदार की असमर्थता जैसी समस्याएं सामने आईं, जिससे परियोजना अधूरी रह गई। परंतु विधायक हेमंत खंडेलवाल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करने का संकल्प लिया। विधायक खंडेलवाल ने नगर पालिका के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं और इस योजना को पूरी तरह से संशोधित कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। नए प्राक्कलन में बेसमेंट पार्किंग, लिफ्ट की सुविधा, हर ब्लॉक में व्यापारियों के लिए सुविधाजनक पहुंच और हाई क्वालिटी की सुविधाएं शामिल की गईं हैं। वर्तमान समय के अनुरूप योजना में जीएसटी दरों को भी समायोजित कर दिया गया है, जिससे अब कोई कानूनी या वित्तीय अड़चन शेष नहीं है। सभी पूर्व से व्यवसाय कर रहे चिन्हित दुकानदारों का व्यवस्थित व्यवस्थापन पूर्व अनुसार किया जायेगा। नगर पालिका द्वारा तैयार की गई संशोधित निविदा में लगभग 300 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें रामलीला मैदान के लिए भी एक स्वतंत्र खंड रखा गया है।

29600 वर्गफीट में बनेगी विशाल पार्किंग - शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशाल पार्किंग एरिया होगा, जो 2758 वर्गमीटर यानी लगभग 29600 वर्गफीट में बनाया जाएगा। इस बेसमेंट पार्किंग में एक साथ 60 कार और 200 बाइक खड़ी की जा सकेंगी, जिससे क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान होगा। 1826.32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक कॉम्प्लेक्स में कुल 300 दुकानें बनाई जाएंगी, जिनमें एच ब्लॉक के अंतर्गत रामलीला मैदान क्षेत्र में 460 वर्गमीटर लगभग 10 हजार स्क्वायर फीट में फैले इस भाग में ओपन आडोटोरियम रामलीला मंच तथा पूरा क्षेत्र कवर्ड रहेगा। व्यापारियों को सुव्यवस्थित व्यापार की सुविधा मिलेगी। योजना में अत्याधुनिक लिफ्ट, प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था के साथ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं, जिससे यह कॉम्प्लेक्स बैतूल के गंज बाजार क्षेत्र को पूरी तरह आधुनिक रूप देने की ओर अग्रसर है।

व्यापारिक आवश्यकताओं का रखा गया ध्यान, टेंडर प्रक्रिया पूरीट्ठविधायक हेमंत खंडेलवाल की लगातार मॉनिटरिंग और प्रयासों से यह प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप ले रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशन में तकनीकी टीम द्वारा एसओआर के अनुसार पूरा संशोधित प्लान तैयार किया गया है और उसमें सभी आधुनिक व्यापारिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। गौरतलब है कि गंज मंडी कॉम्प्लेक्स की योजना एक दशक से व्यापारियों की प्रतीक्षा का केंद्र बनी हुई थी। अधूरा निर्माण व्यापारियों की निराशा का कारण बने हुए थे। लेकिन अब जब इस प्रोजेक्ट को पुन: प्रारंभ करने की स्वीकृति मिल गई है और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो बैतूल के व्यापारियों में भी खुशी की लहर है।

सप्रे संग्रहालय मनाएगा बुजुर्ग पत्रकार श्री प्रेमनारायण नागर की जन्मशती

केंद्रीय मंत्री चौहान का उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने किया आत्मीय स्वागत

मध्यप्रदेश के विकास, कृषक हितैषी योजनाओं के संबंध में की विस्तृत चर्चा

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज भोपाल स्थित निवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के समग्र विकास, विशेषकर किसानों के हित में चल रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मंत्री राकेश शुक्ला ने की सौजन्य भेंट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से डॉ मोहन सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने राजधानी स्थित उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। विधानसभा

अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री राकेश शुक्ला के बीच राजनैतिक, समसामयिक और ग्वालियर- चंबल संभाग के विकास के मुद्दों के साथ पार्टी के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई।

एम्स भोपाल ने प्रतिष्ठित आईआईआरएफ रैंकिंग 2025 में नए एम्स में पहला स्थान पाया,एमपी में दूसरा

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में संस्थान ने आईआईआरएफ विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में;अनौद्योगिकीय एवं गैर-तकनीकी श्रेणी में शोध उत्कृष्टता के लिए देशभर में 31वां स्थान प्राप्त किया है। एम्स भोपाल को मध्यप्रदेश में आईआईएसईआर भोपाल के बाद दूसरा स्थान मिला है तथा सभी नवस्थापित एम्स संस्थानों में यह शीर्ष पर रहा है। यह सम्मान एम्स भोपाल की अकादमिक उत्कृष्टता, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति सतत प्रयासों का प्रमाण है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली है, जो केंद्रीय, डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों का पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित पद्धति से मूल्यांकन करती है। यह प्रणाली कुल 17 उपश्रेणियों में संस्थानों का आंकलन करती है, जिनमें शोध, अकादमिक गुणवत्ता एवं सामाजिक प्रभाव को विशेष महत्व दिया जाता है। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अत्याधुनिक ट्रांसलेशनल रिसर्च और संवेदनशील चिकित्सीय सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं हमारे समर्पित फैकल्टी, स्टाफ और छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिनकी निष्ठा और परिश्रम से यह मुकाम हासिल हुआ है।

स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, सेवा गुणवत्ता और जनविश्वास का समन्वय आवश्यक : उपमुख्यमंत्री शुक्ल

*समस्त स्वास्थ्य संस्थानों को मानक अनुरूप बनाने करें सघन प्रयास *जिला चिकित्सालय सिवनी और देवास कायाकल्प में प्रथम, एनक्यूएएस मापदंड में दतिया शीर्ष पर

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के साथ-साथ स्वच्छता और साफ-सफाई का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल दवा और इलाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अस्पताल परिसर का वातावरण, संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता और मरीजों को मिलने वाली संपूर्ण देखरेख भी उतनी ही आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं ने कायाकल्प, एन.क्यू. ए.एस., मुस्कान और लक्ष्य जैसे कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह प्रमाणित किया है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने स्वर्ण जयंती सभागार नारोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के कायाकल्प, एनक्यूएएस, मुस्कान एवं लक्ष्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को सम्मानित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धियाँ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते कदम हैं। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि बड़ी संख्या में संस्थान इन मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि शेष संस्थाओं को भी इन मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के संपूर्ण सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 10 हज़ार करोड़ की लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग में 3 हज़ार चिकित्सकों सहित कुल 35 हज़ार पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिससे मैनपावर की कमी दूर होगी और सेवा प्रदाय की गुणवत्ता बेहतर होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार का प्रयास है प्रदेश के सभी 12,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान कायाकल्प, एन.क्यू.ए.एस., लक्ष्य और मुस्कान जैसे मानकों पर खरे उतरें, इसके लिए केवल बजट और संसाधनों की नहीं, बल्कि सतत मॉनिटरिंग, संस्थागत प्रशिक्षण और कर्मचारियों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। हर संस्थान को सशक्त और उत्तरदायी बनाकर प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'स्वस्थ भारत' के लक्ष्य की दिशा में मध्यप्रदेश लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है। कायाकल्प अवार्ड जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता और सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता का आधार वही लोग हैं जो अस्पतालों में दिन-रात जनसेवा के लिए समर्पित रहते हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2020 के 175 के मुकाबले घटकर 159 पर आ गई है, जो एक

सकारात्मक संकेत है। परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुधार पर्याप्त नहीं है और अभी हमें बहुत आगे जाना है। इस दिशा में उन्होंने गर्भवती माताओं के शत-प्रतिशत पंजीयन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान और उनके समुचित उपचार के लिए ठोस, योजनाबद्ध और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकी सेवाओं को भी सशक्त बना रही है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों की राय और इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कायाकल्प अभियान की शुरुआत वर्ष 2015-16 में हुई थी, जब केवल 9 संस्थाएं मापदंडों पर खरी उतर सकीं थीं, वहीं वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 675 स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुँच चुकी है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन मात्र संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनविश्वास का प्रतीक है।

सशक्त स्वास्थ्य से ही विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश का स्वप्न होगा पूर्ण: राज्य मंत्री पटेल-लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पूर्ण समर्पण से स्वास्थ्य विभाग का अमला कार्य करें। सशक्त स्वास्थ्य से ही हम विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश का स्वप्न पूर्ण कर पाएंगे। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों और चिकित्सकीय टीम को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि कायाकल्प, एन.क्यू.ए. एस., लक्ष्य एवं मुस्कान पुरस्कारों का उद्देश्य प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, सेवा गुणवत्ता एवं मातृ-शिशु देखभाल में उत्कृष्ट मानक सुनिश्चित करना है। इन पुरस्कारों की शुरुआत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु की गई, जिनके तहत संस्थाओं का मूल्यांकन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। कायाकल्प अवार्ड स्वच्छता, ईको-फ्रेंडली उपायों, अपशिष्ट प्रबंधन और अस्पताल रखरखाव के लिए प्रदान किया जाता है।

एन.क्यू.ए.एस. अवार्ड सेवा की गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा और क्लिनिकल प्रोटोकॉल के पालन के आधार पर दिया जाता है। लक्ष्य अवार्ड सुरक्षित प्रसव सेवाओं के लिए और मुस्कान अवार्ड बाल रोग सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों से स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हुआ है।

कायाकल्प अवॉर्ड -वर्ष 2023-24 के अंतर्गत महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय देवास को जिला चिकित्सालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (रू. 15 लाख), सिविल अस्पताल हजीरा (ग्वालियर) को सीएचसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (रू. 10 लाख), पीएचसी अमलाहा (सीहोर) को सह-विजेता के रूप में (रू. 1 लाख), तथा मक्सी (शाजापुर) और संजयनगर (जबलपुर) स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार (रू. 2 लाख) से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी को जिला चिकित्सालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (रू. 15 लाख), सिविल अस्पताल पाटन (जबलपुर) को सीएचसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (रू. 10 लाख), और पीएचसी पिटोल (झाबुआ) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (रु 2 लाख) प्रदान किया गया।

वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय, सिवनी को प्रथम रनर-अप (87.19 प्रतिशत) तथा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल जिला चिकित्सालय (95.71 प्रतिशत) श्रेणी में 10 लाख एवं रू. 5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया। सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय, जबलपुर को द्वितीय रनर-अप (84.35 प्रतिशत) के रूप में रू. 5 लाख की राशि से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष सीएचसी दौराहा, सीहोर को प्रथम रनर-अप (93.86 प्रतिशत) के रूप में 5 लाख तथा सिविल अस्पताल हजीरा, ग्वालियर को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल सीएचसी (92.86 प्रतिशत) श्रेणी में रू. 2.5 लाख का पुरस्कार मिला।

वर्ष 2024-25 में जिला चिकित्सालय बुरहानपुर को प्रथम रनर-अप (94.61 प्रतिशत) श्रेणी में रू. 10 लाख तथा जिला चिकित्सालय भिंड को द्वितीय रनर-अप (90.76 प्रतिशत) और सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल जिला चिकित्सालय (95 प्रतिशत) श्रेणियों में रू. 5 लाख-रू. 5 लाख के संयुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सीएचसी मानपुर, इंदौर को प्रथम रनर-अप (91.07 प्रतिशत) के रूप में रू. 5 लाख तथा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल सीएचसी (96 प्रतिशत) के लिए रू. 2.5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

एन.क्यू.ए.एस., मुस्कान एवं लक्ष्य कार्यक्रमों में में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को किया गया सम्मानित- जिला चिकित्सालय स्तर पर एन.क्यू. ए.एस. स्कोर के आधार पर 13 जिलों को सम्मानित किया गया, जिनमें जिला चिकित्सालय दतिया (93.60 प्रतिशत), सागर (92.9 प्रतिशत), पन्ना (90.43 प्रतिशत), मुरैना (89.45 प्रतिशत), छिंदवाड़ा (88.61 प्रतिशत), रतलाम और झाबुआ (88 प्रतिशत), अनूपपुर (87.12 प्रतिशत), अलीराजपुर (85 प्रतिशत), सीहोर (84 प्रतिशत), धार (83.81 प्रतिशत), जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल (83त्न) एवं बालाघाट (82.07 प्रतिशत) शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं के सिविल सर्जन सह अधीक्षक को सम्मानित किया गया।

सीएचसी/पीएचसी/यू.पी.एच.सी./उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर भी एन.क्यू.ए.एस. मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इनमें सिविल अस्पताल सिवनी मालवा (95 प्रतिशत), सीएचसी दौराहा सीहोर (95 प्रतिशत), पीएचसी उमरधा नर्मदापुरम (97.58 प्रतिशत), यू.पी.एच.सी. कोलुआकलां भोपाल (99.7 प्रतिशत) और उप स्वास्थ्य केन्द्र आमाहिनौता जबलपुर (98.37 प्रतिशत) प्रमुख हैं। इन संस्थाओं के इंचार्ज चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, गुणवत्ता प्रबंधक, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 8 ज़िला अस्पताल, 21 सीएचसी, 73 पीएचसी और 51 सब हेल्थ सेंटर (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) को कायाकल्प और एनक्यूएएस में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया।

मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि वर्ष-2018 में 14 संस्थानों से वर्तमान में 675 स्वास्थ्य संस्थान कायाकल्प मानकों के अनुरूप हैं। 2067 स्वास्थ्य संस्थान एनक्यूएएस मानक अनुरूप हैं। 266 नवजात एवं शिशु इकाइयों में से 27 और 247 प्रसव केंद्र उत्कृष्ट मानक अनुसार हैं। वर्ष-2030 तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मानक अनुरूप करने के सघन प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से आए चिकित्सकीय सहायक चिकित्सकीय अधिकारी और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

2050 तक 10 बिलियन लोगों को कैसे कराएंगे भोजन

दिल्ली में इंडो ग्लोबल इरिगेशन समिट में एमपी से 12 अफसर होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। जलवायु परिवर्तन के दौर में जल और खाद्य सुरक्षा में तालमेल कैसे बन सकता है और 2050 तक 10 बिलियन लोगों को कैसे भोजन कराया जाए। इन मुद्दों पर मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में इंडो ग्लोबल इरिगेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एमपी से जल संसाधन विभाग के सचिव के अलावा अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री स्तर के 11 अधिकारी शामिल होंगे। ये अफसर एमपी की ओर से प्रजेंटेशन देंगे।

इंटरनेशनल कमिशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज अंडर द एइजिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट द्वारा दिल्ली में इंडो ग्लोबल इरिगेशन समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट के लिए एमपी के 12 अफसरों की टीम जाएगी, जिसमें एक आईएएस अफसर और 11 इरिगेशन इंजीनियर शामिल हैं।

प्रमुख मुद्दे जिन पर होगी चर्चा

उच्च स्तरीय वार्ता: जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल एवं खाद्य सुरक्षा पर चर्चा होगी।
जलवायु परिवर्तन के दौर में जल एवं खाद्य सुरक्षा में किस तरह का सहयोग हो सकता है।
भोजन के लिए जल: 2050 तक 10 बिलियन लोगों को कैसे भोजन कराया जाए।
कनाडा में सिंचाई और जल निकासी आधुनिकीकरण और विस्तार।
जल एवं ऊर्जा संबंध: लचीले भविष्य के निर्माण की कुंजी।
कृषि और सिंचाई क्षेत्रों की आम चुनौतियों को अवसरों में बदलना।
खेतारा: जोखिम में एक हाइड्रोलिक विरासत प्रणाली।
मोरक्को थर्मल उपग्रहों का उपयोग करके सिंचाई प्रबंधन के लिए नई तकनीक।
भारत में सिंचाई की आवश्यकता पर भी मंथन
इस समिट में भारत की सिंचाई की आवश्यकता पर भी मंथन होगा। साथ ही ये मुद्दे भी चर्चा में रहेंगे।
भारत की जल सुरक्षा प्राप्त करना।
जल प्रबंधन के लिए जल-ऊर्जा-खाद्य नेक्सस के तालमेल बनाना।
नमक प्रभावित कृषि भूमि और सिंचाई से कृषि उत्पादन के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्रबंधन योजनाओं की सिफारिश करने के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली।
जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत भारत की सिंचाई की जरूरतें।
सिंचाई क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक अनुप्रयोग।
जल संरक्षण में स्मार्ट सिंचाई प्रणाली पर भी डिस्कशन
पंजाब की जीवन रेखाओं को पुनर्जीवित करना।
पंजाब द्वारा नहर प्रणाली की बहाली।
जल संरक्षण में आईओटी आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली की प्रभावशीलता।
अटल जल पहल मक्का उत्पादन में सिंचाई दक्षता के मूल्यांकन के लिए थर्मल यूएवी निगरानी का अनुप्रयोग।
मिट्टी की नमी की गतिशीलता पर परिशुद्ध सिंचाई का प्रभाव।
जीआईएस का उपयोग करके सिंचाई प्रणाली का मूल्यांकन।
पहाड़ी कृषि वातावरण में मिट्टी की नमी के आकलन के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन यूएवी इमेजरी का उपयोग।
टिकाऊ कृषि के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी और सुधार तकनीक।

नारी सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिमा - मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती जी

स्मृति दिवस पर सुखशांति भवन में पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजन

भोपाल। ब्रह्माकुमारीज़ सुखशांति भवन में 24 जून की संध्या, एक दिव्य, शांत और स्नेहमयी अनुभूति से परिपूर्ण रही। यह अवसर था - मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती जी की पुण्यतिथि का। इस पुण्य स्मरण समारोह में उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व, एक आध्यात्मिक वीरांगना, तथा सच्चे अर्थों में नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सामूहिक मौन और राजयोग ध्यान से हुआ, जिसमें उपस्थित सभी सेवाकेंद्र प्रभारी, वरिष्ठ बहनें, व स्थानीय गणमान्य जनों ने भाग लिया।

सुख शांति भवन के निदेशिका आदरणीय नीता दीदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा मातेश्वरी जी - एक आध्यात्मिक प्रेरणा थीं।

मातेश्वरी जी, जिनका लौकिक नाम राधे था, कम आयु में ही परमात्मा शिव के दिव्य कार्य में समर्पित हो गईं। ज्ञान की गहराई, वैराग्य की तीव्रता और मातृत्व की माधुर्यता - इन तीनों का अनुपम संगम उनके जीवन में झलकता था। ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में आत्मसात कर, उन्होंने एक साधारण गृहिणी से लेकर ब्रह्माकुमारी संस्था की प्रथम मुख्य संचालिका बनने तक की यात्रा अत्यंत सादगी, निष्ठा और शक्ति से पूरी की।

कार्यक्रम के दौरान आदरणीय नीता दीदी जी ने भावुक होकर कहा, जब मातेश्वरी जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं, तब भी उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि आत्म-शांति और स्थिरता की दिव्य चमक दिखाई देती थी। जैसे वह शरीर की नहीं, आत्मा की स्थिति में स्थित थीं। उनका कहना होता - यह देह नश्वर है, पर आत्मा अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मा की शक्ति से बीमारी भी माया जैसी लगती है। वहीं ब्रह्मकुमारी आराधना बहन ने बताया कि मातेश्वरी जी का संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा, सहनशीलता, और नि:स्वार्थ प्रेम से ही कोई स्त्री जगदंबा बनती है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी देती है।

उन्होंने कहा मातेश्वरी जी की वाणी में गूढ़ ज्ञान होता था, पर वह उसे इतने सहज और मातृत्वपूर्ण ढंग से समझातीं कि हर उम्र का व्यक्ति उसे आत्मसात कर लेता। उनके व्यवहार में कभी कटुता नहीं होती, केवल करुणा होती। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल बोलने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने की शैली है। साथ ही आदरणीय ज्योति दीदी जी ने यह भी कहा कि मातेश्वरी जी ने हर घड़ी, अंतिम घड़ी' की नीति को आत्मसात कर संस्थान को एक मजबूत नींव दी। उनका कहना था कि हमें हर घड़ी को इस प्रकार जीना चाहिए जैसे यह हमारी अंतिम संशोधन एवं परमात्मा की याद में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर सबको सुख देना चाहिए। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षा आज हर ब्रह्माकुमारी बहन के जीवन में जीवित है।

मातेश्वरी जी का जीवन आज की हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल बाह्य सशक्तिकरण ही नहीं, आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही सच्ची शक्ति देता है। कठिनतम परिस्थितियों में भी, यदि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो, तो वह न केवल स्वयं को सम्भालती है, बल्कि सैकड़ों को सम्भाल सकती है।

डॉ. मुखर्जी के बलिदान से खड़ी हुई पार्टी, पं.दीनदयाल जी ने दिया विचार : विष्णुदत्त शर्मा

* देश की अखंडता, अनुसूचित जाति के हितों के लिए डॉ. मुखर्जी ने की थी जनसंघ की स्थापना * प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया डॉ. मुखर्जी का संकल्प

भोपाल। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के करूणाधाम मण्डल के बूथ क्रमांक 54 स्थित संत रविदास मंदिर में दर्शन कर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक क्रांतिकारियों के बलिदानों के आधार पर देश को 1947 में आजादी मिली। लेकिन देश में पं. नेहरू के नेतृत्व में जो पहली सरकार बनी, उसने यह निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान लागू नहीं होगा।

भारत का प्रधानमंत्री अलग होगा, कश्मीर में वजीरे आजम अलग होगा। देश का संविधान और ध्वज अलग होगा, कश्मीर का अलग होगा। कश्मीर में धारा 370 लगा दी गई। उस समय नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। धारा 370

में यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में किसी सफाइकर्मी का बेटा अपनी योग्यता के आधार पर भी कोई पद नहीं पा सकता और उसे जीवनभर सफाईकर्मी ही रहना होगा। डॉ. मुखर्जी ने कहा एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। अनुसूचित जाति के हितों पर प्रहार नहीं चलेगा। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना की।

भाजपा की सरकार ने पूरा किया डॉ. मुखर्जी का संकल्प

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल में ही डॉ. मुखर्जी की हत्या कर दी गई। श्री शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय अटलजी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं था, इसलिए धारा 370 को हटाया नहीं जा सका। जब 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जब धारा 370 हटाने को लेकर संसद में बहस चल रही थी, तब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने कहा था कि अगर धारा 370 हटाई गई, तो देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसकी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है।

अंत्योदय के विचार पर चलकर भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा जो आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान के आधार पर खड़ी हुई है। इस पार्टी को पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार दिया है। उनके दिये अंत्योदय के विचार पर चलते हुए भाजपा आज यहां तक पहुंची है। श्री शर्मा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी जब पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के गांव नगला चंद्रभान पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक स्मारक पं. दीनदयाल जी की झोपड़ी का चित्र देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि देश का कोई गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान दिये जा चुके हैं और 3 करोड़ परिवारों को आने वाले समय में पक्के घर दिये जाएंगे। अंत्योदय के विचार से प्रेरित होकर ही आयुष्मान भारत और गरीब कल्याण की अन्य योजनाएं शुरू की गईं। श्री शर्मा ने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण की ये योजनाएं इसलिए सफल हो रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गरीब मां के बेटे हैं और झोपड़ी में रहने वालों का दर्द पहचानते हैं। कार्यक्रम को पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने भी सम्बोधित किया।इस दौरान अहिरवार समाज के अध्यक्ष श्री सुबाराम घनोते, कार्यक्रम संयोजक श्री संतोष ब्रम्हभट्ट, श्री योगेश परमार, मंडल अध्यक्ष श्री मुकेश जिहाडी एवं बूथ अध्यक्ष श्रीमती ज्योति जाधव मंच पर उपस्थित रहीं।

राइट क्लिक

ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत, कितनी जायज?

अजय बोकिल

मिर्यां गालिब कह गए हैं कि 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले..।' ऐसे में अगर मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति का नोबेल प्राइज पाने की हसरत और वो भी बिना कुछ खास किए पाले तो गलत क्या है? ये जमाना ही शॉर्ट कट का है, लिहाजा लोग उंगली कटाकर भी शहीद बनना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का दर्द यही है कि अपने दूसरे कार्यकाल के सात महीनों में उन्होंने दुनिया की बेहतरी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कोई इसका कदरदान ही नहीं है, सिवाय एक पाकिस्तान के। जिसने एक क्रिप्टो डील और भारत के साथ कथित रूप से ट्रंप की पहल पर हुए सीजफायर की ऐवज में ट्रंप बाबा को नोबेल का सुपात्र घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नोबेल पुरस्कार किसी के चाहने भर से मिल सकता है? क्या यह भक्त को भगवान के वरदान की तरह है या फिर किसी सोद्देश्य, सद्भावनापूर्ण जीवन, असाधारण साधना, समर्पण और प्रतिबद्धता की वैश्विक स्वीकृति है, जिसके मिलने से मानव जीवन एक महान चरित्र और आदर्श में परिणत हो जाता है? शायद हां। यही कारण है कि तमाम तरह के सौदेबाजियों में लिप्त और विश्वनीयता शब्द को तार-तार करने वाले ट्रंप अब नोबेल पुरस्कार पाकर विश्व इतिहास में अमर हो जाना चाहते हैं। इसकी खास वजह तो उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ओबामा हैं, जिन्हें दुनिया में शांति और सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ट्रंप उसे अपने तरीके से झटक लेना चाहते हैं।

याद करें कि 1957 में एक फिल्म आई थी, नाम था 'हुलाकू।' वो क्रूर मंगोल शासक जिसने इस्लाम खलीफाओं की अब्बासिद शाखा की राजधानी बगदाद की ईंट से ईंट से बजा दी थी और खलीफा परंपरा को ही खत्म कर दिया था। उसी फिल्म में लता मंगेशकर का गाया गीत है' दिल का ना करना ऐतबार कोई।' यही गीत अब कुछ नए अंदाज में इतिहास दोहराता लगता है कि 'अमेरिकी राष्ट्रपति 'डोनाल्ड ट्रंप पर करना ना ऐतबार कोई...!' क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। कब क्या कर बैठे, कह बैठे। कब पलटीमार दे और कब यू-टर्न ले ले। इसका ताजातरीन उदाहरण इजराइल है, जो ट्रंप की शह पर ईरान से पंगा लेकर फंस गया लगता है। शायद अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका 45 राष्ट्रपति इतना अस्थिर चित्त, अविश्वसनीय, गजब का सौदेबाज और पल पल में रंग बदलने वाला साबित होगा। इस पर तुर्रा यह कि बतौर राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए और इसके लिए उनके नाम की सिफारिश वो पाकिस्तान कर रहा है, जो पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सशस्त्र कार्रवाई को कथित तौर पर रूकवाने के लिए ट्रंप के एहसान तले दबा हुआ है, वही पाकिस्तान जिसने अपने एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. दारे सलाम की कभी कद्र नहीं की, क्योंकि वो अहमदिया मुसलमान थे। उधर राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने अपनी जो 'वैश्विक उपलब्धियां' गिना रहे हैं, उनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मिलकर कांगो और रवांडा के बीच समझौता कराना, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रूकवाना, सर्बिया और कोसोवो के बीच अमन की कायमी, मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाने तथा मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अब्राहम समझौता कराना आदि है। फिर भी उनका दर्द कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। और मेरे लिए यही सबसे जरूरी है।

ट्रंप के दावे अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप की रूस-यूक्रेन के बीच शांति कराने में नाकामी, ईरान-इजराइल के युद्ध को रूकवाने में उनकी विवादास्पद भूमिका, टैरिफ के नाम पर तमाम देशों के साथ अलग-अलग डील का ड्रामा, अमेरिका फर्स्ट की आड़ में एक के बाद एक अदूरदर्शी फैसले और विचित्र तर्क, राष्ट्रपति पद की गंभीरता को रसातल में ले जाना, दोस्तों से दुश्मनी भरा बरताव (जैसे कि भारत) और दुश्मनों को निजी फायदों के लिए गले लगाना (जैसे कि पाकिस्तान)। कभी चीन को दुश्मन नंबर एक बताना तो उसी के साथ टैरिफ और रेयर अर्थ एलीमेंट सप्लाई समझौता कर लेना, जिस खरबपति इलान मस्क को उन्होंने सबसे करीबी दोस्त बताया, उसी को किनारे लगाना, यह भ्रम बनाए रखना कि ट्रंप को अमेरिका का डीप स्टेट चला रहा है या ट्रंप डीप स्टेट को चला रहे हैं, खनिज संसाधनों की ब्लैकमेलिंग को नया राजनीतिक अस्त्र बनाना, पारिवारिक धंधे के विस्तार के लिए राष्ट्रपति पद का यथासंभव दोहन करना तथा नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर व्यावसायिक मूल्यों को तरजीह देना आदि हैं।

तो क्या सचमुच ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, क्या वे इसके लिए पात्र हैं? ट्रंप के बेटे की कंपनी के साथ क्रिप्टो करेंसी धंधे का समझौता करने वाले पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश की नोबेल कमेटी की निगाह में क्या अहमियत होगी? जहां तक नोबेल पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश का प्रश्न है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को मिलता है, जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, सैन्य तनाव घटाने और शांति स्थापना के लिए असाधारण काम किया हो। नोबेल पुरस्कार के लिए हर साल एक फ़रवरी तक नामांकन जमा लिए जाते हैं। नामांकन प्रक्रिया 8 महीने तक चलती है। इसका संचालन नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है। इस पांच सदस्यीय नोबेल समिति की नियुक्ति नॉर्वे की स्टॉर्टिंग (संसद) करती है। केवल चुनिंदा लोग और संस्थाएं ही किसी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकते हैं, जैसे- देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विश्वविद्यालयों के प्रोफ़ेसर, पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, संसद सदस्य, जज और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य आदि। ये लोग अपने नामांकन में यह बताते हैं कि क्यों फलां व्यक्ति या संगठन शांति पुरस्कार का हक़दार है। नामांकन फार्म 31 जनवरी तक जमा होते हैं। प्राप्त नामांकनों की जांच नोबेल समिति जांच करती है और एक शॉर्टलिस्ट तैयार करती है। समिति विशेषज्ञों से सलाह ले सकती है और सूक्ष्म जांच और विचार-विमर्श के बाद विजेता का नाम चुनती है। आमतौर पर विजेता के नाम की घोषणा हर साल अक्टूबर में होती है। समिति का निर्णय अंतिम होता है। पुरस्कार के लिए समिति के पास जो नाम भेजे जाते हैं, उन्हें 50 साल तक गोपनीय रखा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को ओस्लो, नॉर्वे में होता है, जहां विजेता को मेडल, सर्टिफ़िकेट और नकद पुरस्कार राशि (लगभग साढ़े 8 करोड़ रुपये) दी जाती है। बाकी के छह नोबेल पुरस्कार (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, साहित्य और अर्थशास्त्र) स्वीडन की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नोबेल समिति के पास कुल 338 नाम आ चुके हैं, जिनमें से 244 व्यक्तिगत और 94 नाम संगठनों ने भेजे हैं। अगर ट्रंप नोबेल की चाहत रखें भी तो उन्हें 2026 का इंतजार करना होगा।

असल में ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार पाना उनकी अपनी सनकभरी कार्यशैली को वैश्विक वैधता दिलाने की दिली हसरत है। वरना नोबेल पुरस्कार की साढ़े 8 करोड़ रू. की राशि उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। फोर्ब्स के अनुसार ट्रंप की कुल सम्पत्ति करीब 5 अरब अमेरिकी डॉलर की बताई जाती है, जिसमें उनके राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही दोगुना इजाफा हुआ है। प्रश्न यह भी है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने की इतनी आस क्यों है? इसका जवाब अमेरिका के उन चार पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा शांति, वैश्विक सदभाव और मानवता के लिए किए गए कार्य हैं, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। मसलन अमेरिका के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को यह सम्मान 1906 में रूस और जापान के बीच युद्ध रूकवाने के लिए दिया गया। रूजवेल्ट ने शांति का संदेश देने एक 'महान श्वेत ध्वज समुद्री बेड़ा' भी दुनिया में भेजा। दूसरे नोबेल विजेता अमेरिकी राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन के खाते में पहले विश्व युद्ध में अमेरिकी तटस्थता तथा विश्व युद्ध रूकवाने में अहम भूमिका के लिए 1919 का नोबेल शांति पुरस्कार आया। विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम भी दिया, जिसमें दुनिया के समुद्र में व्यापारिक जहाजों का मुक्त आवागमन, व्यापारिक रिश्तों में समानता, दुनिया में हथियारों में सहित कई बिंदु शामिल थे। उन्होंने पहली बार वैश्विक संवाद के लिए राष्ट्रों का संगठन बनाने का सुझाव दिया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्वज 'लीग ऑफ नेशन्स' के रूप में सामने आया। तीसरे नोबेल पुरस्कार (2002) पाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे। उन्हें मिस्र और इजराइल के बीच शांति के लिए कैम्प डेविड समझौता कराने तथा लोकतंत्र व मानवाधिकार को मजबूत करने का श्रेय जाता है। चौथे राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं, जिन्हें दुनिया में शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए असाधारण कूटनीतिक प्रयास व सहयोग के लिए (2009) नोबेल पुरस्कार मिला। गौरतलब है कि नोबेल विजेता चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से तीन डेमोक्रेट और केवल एक रिपब्लिकन थे। ट्रंप भी रिपब्लिकन हैं।

नोबेल पुरस्कार पाने की जो बुनियादी पात्रता है, ट्रंप उसमें कितना फिट बैठते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। हकीकत में ट्रंप एक तरफ वैश्विक शांति की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन को धमका रहे हैं। चीन को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताकर उसके साथ ट्रेड डील भी कर रहे हैं। विश्व में शांति के पैरोकार रहे भारत को ठेंगा दिखाकर दुश्मन पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो बिजनेस की प्राइवेट डील कर रहे हैं। जिस 'नाटो' की स्थापना अमेरिका की पहल पर हुई थी, उसी से अमेरिका के तलाक की पैरवी कर रहे हैं। शांति और मानवता के काम करने वाले तमाम वैश्विक संगठनों की आर्थिक मदद बंद कर अमेरिका को शुद्ध मुनाफाजीवी देश बनाने की उनकी जिद है। ट्रंप ने अपनी अविश्वसनीय शैली से पहले यूक्रेन को उलझाया अब इजराइल के सामने मुश्किलों का पहाड़ है। वैश्विक भाई-चारा तो दूर, अब अमेरिका के लिए पक्के दोस्त और दुश्मन का भी कोई मतलब नहीं है। जो ट्रंप की शर्तों पर धंधा करने राजी हो, वह दोस्त और जो झुकने से इंकार करे, वो दुश्मन। दरअसल ट्रंप अमेरिकी सत्ता के नैतिक पतन का एक बुरा उदाहरण हैं, भले ही वो उसे न मानें। अगर नोबेल समिति ने किसी दबाव में ट्रंप को शांति का पुरस्कार देने की 'महाभूल' की तो समझिए कि दुनिया में अब शांति, मानवता, परस्पर सहयोग और अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की परिभाषा भी बदलनी होगी।

● लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

मुख्यमंत्री यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की औरप्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक आज वाराणसी में

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव भी शामिल होंगे

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक मंगलवार, 24 जून को वाराणसी में पहली बार होने जा रही है। इस अहम बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे।मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक वाराणसी के होटल ताज में होगी। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

डीजीपी का फरमान भी बौना साबित

मध्य प्रदेश अजब है पर प्रदेश की पुलिस भी गजब। पुलिस के मुखिया फरमान जारी करते हैं कि पुलिस थाना वह अन्य स्थानों पर सालों से जमे पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के तत्काल तबादले किए जाएं लेकिन उनके इस फरमान का मंत्रालय में सालों से जमे पांच दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों पर कोई असर नहीं होता है। साठ से अधिक पुलिसकर्मी गृह विभाग की विभिन्न शाखों में सालों से पदस्थ हैं और कुछ शाखों के तो प्रभारी तक बन बैठे हैं और उस शाखा के कंप्यूटर आईडी-पासवर्ड के तक हथिया लिए हैं। लेकिन डीजीपी का फरमान इन पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होता है ।मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि गृह विभाग में 60 से अधिक पुलिसकर्मी सालों से गोंद की तरह चिपक गए हैं। अब उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि वह अपना पुलिसिया रवैया गृह विभाग में आने वाले आगंतुकों के साथ भी करने लगे हैं और उन्हें अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण भी मिल रहा है। तबादलों की तारीख तो निकल गई है लेकिन इन पुलिसकर्मियों के सामने डीजीपी का फरमान बौना साबित हो गया।

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

प्रमुख सचिव का वारंट

शिक्षा से जुड़े एक अवमानना मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव के खिलाफ उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने वारंट जारी किया है। 2 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई होनी है। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा से संबंधित विभाग के जिला अधिकारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन व अन्य मदों में भुगतान की अदायगी को लेकर कोर्ट ने करीब 4 साल पहले आदेश जारी किया था। आदेश का पालन न होने पर सेवानिवृत्ति जिलाधिकारी ने न्यायालय में अवमानना याचिका लगाई। जिस पर भी 2 साल का वक्त गुजर गया। सुनवाई में उच्च न्यायालय की ग्वालियर ब्रांच में प्रमुख सचिव वअन्य अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर 2 जुलाई को तलब किया है। बता दे की प्रमुख सचिव महिला अधिकारी है।

'अगवानी' नेता

दल बदल कर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए एक वरिष्ठ नेता अपने आप को रिसीविंग नेता स्थापित करना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि दल बदलू नेता, केंद्रीय मंत्री हो या भाजपा का कोई अन्य कोई वरिष्ठ पदाधिकारी उसे रिसीव करने स्टेट हैंगर या बैरागढ़ विमानतल अवश्य पहुंच जाते हैं और पुष्प कुछ भेंट कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। दल बदलू नेता इस दौरान फोटोग्राफरों को भी इशारे से यादगार पल की फोटो खींचने का भी कहते हैं। सूत्र बताते हैं कि दल बदलू नेता को भाजपा ने कोई महत्वपूर्ण की जिम्मेदारी नहीं दी है। इसके चलते वह पार्टी में अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरह दर्ज कराने स्टेट हैंगर या विमानतल पर पहुंच ही जाते हैं जबकि भाजपा में केंद्रीय मंत्री हो या पार्टी का अन्य पदाधिकारी की अगवानी के लिए प्रोटोकॉल के तहत ड्यूटी लगाई जाती है।

एमडी की मीटिंग, कामकाज प्रभावित

प्रदेश सरकार के एक निगम के प्रबंध संचालक की कार्यप्रणाली पर वहीं के अधिकारी और कर्मचारी सवाल उठने लगे हैं। निगम के रूटीन कामकाज प्रबंध संचालक की मीटिंग के चलते प्रभावित होने लगे हैं। वहीं नई योजनाएं भी को लेकर प्रबंध संचालक को कोई रुचि नहीं है। सूत्र बताते हैं कि संचालक समय के बड़े पाबंद है लेकिन मीटिंग के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। निगम की पुरानी योजनायें जैसे तैसे चल रही है और नई योजनाओं के लिए कोई विजन सामने नहीं आया। बता दें कि यह निगम, प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना से संबद्ध है और इस पर कुछ हद तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जिम्मेदारी है।

सड़क निर्माण

- ऋतुराज बुड़ावनवाला
(वरिष्ठ पत्रकार और फोटोग्राफर)

इंदौर-खंडवा रोड की धीमी गति आखिर कब तक

इंदौर से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों में इंदौर-खंडवा-एदलाबाद का 216 किलोमीटर का लंबा मार्ग भी है। सालों से यह सड़क ख़राब थी, जिसका काम अगस्त 2022 में शुरू हुआ था और इस साल जनवरी में इसे पूरा होना था, पर नहीं हुआ। अब इसे फ़रवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पर, जिस तरह से काम की गति है, इसमें भी संशय व्यक्त किया जा रहा है। जितना काम बाकी है, काम की गति उतनी तेज नहीं दिखाई।

इंदौर-खंडवा-एदलाबाद 216 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन का बनाया जा रहा है। इस परियोजना का काम अगस्त 2022 में शुरू हुआ था और इसे जनवरी 2025 तक पूरा होना था। लेकिन, काम धीमा होने से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर अब फरवरी 2026 कर इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भेरूघाट और चोरल घाट पर होने वाली दुर्घटनाओं से तथा घंटो तक लगने वाले जाम से राहत मिलेगी तथा खंडवा और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले आम लोगों को यातायात में सुविधा होगी।

इस मार्ग पर सबसे अहम हिस्सा तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक का 33 किमी का है। घाट सेक्शन पर पुल-पुलिया, फ्लाई ओवर बन रहे हैं। इस हाईवे पर तीन सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। जिसका काम अभी भी काफी बाकी है। इन सुरंगों का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भेरूघाट सुरंग (लंबाई 576 मीटर), बाई ग्राम सुरंग (480 मीटर) और चोरल घाट सुरंग (550 मीटर) का काम लंबे समय से चल रहा है। टनल आर-पार होने के बाद छत समेत तीनों ओर को सीमेंट-कांक्रीट से उसे पक्का किया जा रहा है। टनल की फिनिशिंग के लिए 42 खिड़कियों वाली गेंट्री से सीमेंट-कंक्रीट का प्लास्टर किया जा रहा है।

रेलवे की पटरियों जैसे बेस पर गेंट्री लगाई है, जो एक दिन में 12.5 मीटर सीमेंट-कांक्रीट कर देती है। 42 खिड़कियों और टनल की दीवार के बीच 2.5 मीटर की गैप में सरियों का जाल है। एक खिड़की से सीमेंट-कांक्रीट भरने के बाद दूसरी खिड़की से जब मटेरियल निकलने लगता है तो उसे बंद कर देते हैं। इस तरह टनल को पक्का किया जा रहा है। टनल में सड़क बनाने के लिए बेस बना दिया गया है। तीनों टनल एनएटीएम (न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड) तकनीक से बनाई जा रही है। इस ऑटोमेटिक टनल में कई अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में बैरिकेड्स बंद हो जाएंगे। साथ ही आग बुझाने के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। यदि यह काम समय पर पूरा हो जाता है, तो भारी वाहनों को दिसंबर से हाईवे से गुजरने की अनुमति मिल जाएगी। सिमरोल बायपास और सिमरोल अंडरपास को भी बारिश के पहले शुरू करने की तैयारियां थी, किंतु काम अभी भी अधूरा है। दरौंदा के पास बनाए गए फ्लाईओवर से ट्रैफिक शुरू हो चुका है। जैसे-जैसे काम होता जा रहा है, वैसे-वैसे एनएचएआई सड़क पर ट्रैफिक शुरू करती जा रही हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने वाले भक्तों को इस हाईवे के बनने से बहुत लाभ होगा। घाट सेक्शन और कर्व के कटाव से इंदौर से खंडवा की दूरी और यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। इंदौर से खंडवा दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा। नवनिर्मित सड़क पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 से 100 कि.मी.प्रति घंटा रहेगी। अभी इंदौर-खंडवा दो लेन पर यातायात हमेशा ही जाम रहता है। महाकाल लोक के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वे उज्जैन के साथ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में सड़क मार्ग से सफर करते हैं।

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य : राज्यमंत्री श्रीमती गौर

गोविंदपुरा क्षेत्र में 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने से कार्य में कोई बाधा नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जनता के सेवक हैं। जनप्रतिनिधि एक जनसेवक होता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता का साथ और विकास का संकल्प - यही मेरी प्रतिबद्धता है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने सोमवार को गोविंदपुरा क्षेत्र में 70 लाख रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने रजत विहार कॉलोनी में 5 लाख रुपए की लागत से पेविंग ब्लॉक निर्माण कार्य और 7 लाख रुपए की लागत से सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा की अमर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 4 लाख रुपए की लागत पेवर ब्लॉक कार्य का निर्माण कराया जाएगा।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि गोविन्दपुरा क्षेत्र के वार्ड 54 के दुर्गा नगर मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक और मंदिर की छत डलने के निर्माण कार्य का भूमिपूजन क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में किया।